



पीएम का दौरा 'रिच और प्रोडक्टिव': विदेश सचिव

प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने 'रिच और प्रोडक्टिव' बताया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से कुछ अधिक समय की यह यात्रा छोटी जरूर थी, लेकिन उपलब्धियों के लिहाज से बेहद समृद्ध रही। विदेश सचिव ने कहा कि यह दौरा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर हुआ और इससे भारत-इजराइल संबंधों को नई दिशा मिली है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वे पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के रिश्तों को सक्रिय रूप से मजबूत कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री कुवेत, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान और अब इजराइल की यात्रा कर चुके हैं।

मोदी बोले, इजराइल का संसदीय सम्मान देने के लिए शुक्रिया

मोदी ने कहा कि कल मुझे इजराइल की संसद को संबोधित करने का मौका मिला। वहां मुझे स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान के लिए नेसेट के स्पीकर और मेरे मित्र पीएम नेतन्याहू और इजराइल के लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और इसे 140 करोड़ भारतवासी और भारत इजराइल मित्रता को समर्पित करता हूँ।

इजराइल में भारतीय यूपीआई चलेगा

मोदी-नेतन्याहू की बैठक में समझौता: मोदी बोले, जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इजराइल आना मेरे लिए गर्व की बात

जन एक्सप्रेस/एजेसी। तेल अवीव

प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल दौरे का आज आखिरी दिन है। मोदी दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले यरूशलम के होलोकॉस्ट मेमोरियल 'याद वाशेम' पहुंचे। यहां उन्होंने हिटलर के नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। इस दौरान इसाक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। वहीं, पीएम मोदी ने इजराइली राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया। फिर पीएम मोदी और इजराइली पीएम नेतन्याहू ने द्विपक्षीय मीटिंग के बाद जॉर्डन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया गया है कि इजराइल में भी अब भारत का यूपीआई एपेट सिस्टम चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। मोदी बुधवार को इजराइल पहुंचे थे। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिस्वी किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने इजराइली संसद नेसेट को भी संबोधित किया। उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' दिया गया। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।



हिटलर के शासन में मारे गए यहूदियों की याद में बना 'यद वाशेम' स्मारक

याद वाशेम होलोकॉस्ट के दौरान मारे गए लाखों यहूदियों की याद में बनाया गया है। यह स्मारक इजराइल की राजधानी यरूशलम में स्थित है और हर साल दुनिया भर से लोग यहां आकर इतिहास को समझते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी। इस नरसंहार को होलोकॉस्ट कहा जाता है। इजराइल की संसद नेसेट ने साल 1953 में फैसला किया कि होलोकॉस्ट में मारे गए लोगों की याद में एक खास स्मारक बनाया जाए। बाद में 2005 में यहां एक आधुनिक संग्रहालय खोला गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस त्रासदी को समझ सकें। याद वाशेम परिसर में होलोकॉस्ट संग्रहालय, हॉल ऑफ नेम्स, बच्चों का स्मारक और राइटिंग्स अमंग द नेशंस गार्डन जैसी जगह मौजूद हैं। यहां असली दस्तावेज, तस्वीरें और पीड़ितों की व्यक्तिगत कहानियां सुरक्षित रखी गई हैं। याद वाशेम नाम का अर्थ है याद और नाम, यानी जिन लोगों को मिटाने की कोशिश की गई, उनकी याद हमेशा जिंदा रहे।

भारत और इजराइल के बीच 16 एमओयू और समझौते साइन हुए

मिस्त्री ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद करीब 16 एमओयू और समझौतों का आदान-प्रदान हुआ। ये समझौते विज्ञान, तकनीक, नवाचार, साइबर सिक्योरिटी, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत-इजराइल संबंधों को 'स्पेशल स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी' तक अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास और मजबूत साझेदारी का प्रतीक है।

'मोदी इजराइली संसद का सम्मान पाने वाले पहले शख्स'

विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि भारत-इजराइल संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए पीएम मोदी को इजराइली संसद का सम्मान मिला। 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' पाने वाले पीएम मोदी पहले शख्स हैं। मिस्त्री ने बताया कि आज सुबह पीएम मोदी ने यद वाशेम, वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्ब्रंस सेंटर में होलोकॉस्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति भवन परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत ओक का पौधा लगाया। पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातों में दोनों देशों ने विज्ञान, तकनीक, नवाचार, साइबर सिक्योरिटी, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत जताई।

मोदी बोले, दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। किसी भी रूप में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम अब तक कथे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता भारत की सुरक्षा से सीधे जुड़ी है। इसलिए हमने हमेशा बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की भी मांग है। गाजा पीस प्लान से शांति की दिशा में एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूरा समर्थन किया है। आगे भी हम सभी देशों के साथ बातचीत और सहयोग जारी रखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआईआरटी से कहा, माफी काफी नहीं हार्ड कॉपी वापस लें, डिजिटल कॉपी हटाएं



जन एक्सप्रेस/एजेसी। नई दिल्ली

एनसीआईआरटी की आठवीं कक्षा की किताब के विवादित अंश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान एनसीआईआरटी की आठवीं की उस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला हिस्सा है। किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' वाले अंश को लेकर उपजे विवाद पर चीफ जस्टिस सुर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागवी और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में एनसीआईआरटी का माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी किताब बच्चों तक जाने देना गलत होगा। न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। शिक्षा सचिव और एनसीआईआरटी को नोटिस जारी करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट संतुष्ट नहीं हो जाता, सुनवाई जारी रहेगी।

एनसीआईआरटी के निदेशक को कारण बताना होगा

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस किताब की सभी कॉपीयों को जबरन हटाने का आदेश दिया है और साथ ही इसके डिजिटल प्रिंट को भी हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर उसके इस आदेश के पालन में कोताही बरती गई तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी।
- सर्वोच्च अदालत ने एनसीआईआरटी के निदेशक, स्कूल शिक्षा सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये पूछा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुर्यकांत ने कहा कि यह न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का लिए जानबूझकर किया गया कृत्य लगता है।
- सुनवाई के दौरान एनसीआईआरटी ने कहा कि वे बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। किताब से विवादित अंश को ही हटा दिया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि केवल माफी मांगना और किताब से आपत्तिजनक अंशों को हटाना पर्याप्त नहीं है। एनसीआईआरटी के निदेशक को कारण बताना होगा। ये सोच-समझकर उदाया गया कदम है। अदालत ने सवाल किया कि इस मामले को अवमानना क्यों नहीं माना जाए?
- पीठ ने कहा कि मामला आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है। हम इसकी विस्तृत जांच चाहते हैं।
- अदालत ने कहा कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे लोगों का न्यायपालिका में विश्वास कमजोर होगा। किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 मार्च तक टाल दी है।

'किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं'

- गौरतलब है कि बुधवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिबल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने सीजेआई के सामने यह मामला उठाया था। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुर्यकांत ने एनसीआईआरटी किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर पर कड़ी नाराजगी जताई। सीजेआई ने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
- नाराजगी जाहिर करते हुए सीजेआई ने कहा, 'संस्था का प्रमुख होने के नाते मैंने हमेशा अपने दायित्व को निभाया है। मैं किसी को इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि न्यायपालिका को बदनाम करें। किसी कीमत पर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, कोई किताब भी बड़ा क्यों नहीं हो। कानून अपना काम करेगा।' मैं जानता हूँ कि इससे कैसे निपटा जाए। मैं स्वतः सज्जन ले रहा हूँ।
- दरअसल, एनसीआईआरटी ने 24 फरवरी को कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब जारी की, लेकिन किताब के एक अध्याय में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' का एक सेक्शन था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद एनसीआईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) ने माफी मांगी है और विवादित चैप्टर वाली कक्षा 8 की किताब के वितरण पर रोक लगाई है।
- मामला सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तुरंत निर्देश दिया कि अगली सूचना तक इस किताब का वितरण रोक दिया जाए। एनसीआईआरटी ने आदेश मानते हुए किताब की आपूर्ति पर रोक लगा दी है।

भ्रष्टाचार वाले विभाग के अधिकारी ही जांच टीम में शामिल, उठे निष्पक्षता पर सवाल

जन एक्सप्रेस। शत्रुघ्न सिंह

उरई। जिला मुख्यालय स्थित भूमि संरक्षण अधिकारी राष्ट्रीय जलाम उरई कार्यालय और डीडी कार्यालय में चिकित्सा प्रतियुक्ति के नाम पर लाखों रुपये के कश्चित फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक ओर दो कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सबसे अहम प्रश्न यह उठ रहा है कि जिन विभागों से कश्चित गोलमाल करने की कोशिश तो नहीं? नगर में इस बात को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है और लोग इसे जांच की पारदर्शिता से जोड़कर देख रहे हैं।

अन्य विभाग भी शक के घेरे में

सूत्रों की मानें तो जन्मपद के कई अन्य विभागों में भी चिकित्सा प्रतियुक्ति के मामलों में अनियमितताओं की फाइलें दबे होने की चर्चा है। यदि वर्तमान मामले की गहन जांच होती है, तो कई और विभागों के नाम सामने आ सकते हैं। इसी संभावना ने संबंधित विभागों के कर्मचारियों, विशेषकर लिपिक वर्ग में बेवैनी बढ़ा दी है। चर्चा है कि कई स्थानों पर पुराने अभिलेखों को खंगाला जा रहा है और दस्तावेजों को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है।

दो कर्मचारियों पर दर्ज हुई एफआईआर

जानकारी के अनुसार, चिकित्सा प्रतियुक्ति के नाम पर कागजी हेराफेरी कर लाखों रुपये निकालने के आरोप में भूमि संरक्षण अधिकारी राष्ट्रीय जलाम उरई कार्यालय में तैनात श्यामजी (वरिष्ठ सहायक) तथा डीडी कार्यालय के हर्ष वर्मा (कनिष्ठ सहायक) के विरुद्ध दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। बताया जा रहा है कि चिकित्सा बिलों और प्रतियुक्ति प्रक्रिया में दस्तावेजों की हेराफेरी कर सरकारी धन का दुरुयोग किया गया। जांच में प्रस्ताविक स्तर पर अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज किया गया।

जांच टीम पर उठ रहे सवाल

हालांकि कार्रवाई के बाद भी जनता के मन में एक संशय बना हुआ है। नगरवासियों का कहना है कि यदि उसी विभाग के अधिकारी जांच टीम का हिस्सा होंगे, जहां से अनियमितताओं की शुरुआत हुई, तो क्या जांच निष्पक्ष और पारदर्शी रहे जाएगी? लोगों का मानना है कि निष्पक्ष जांच के लिए बाहरी अथवा स्वतंत्र एजेंसी को शामिल किया जाना चाहिए था। अन्यथा, मामले के पूर्ण खुलासे के बजाय इसे सीमित दायरे में समेटे जाने की आशंका बनी रहेगी।

पारदर्शिता की मांग तेज

नगर के जागरूक नागरिकों का कहना है कि जांच निष्पक्ष और व्यापक रूप से की जाती है, तो यह पूरे जन्मपद में एक साकारत्मक संदेश देगा। वहीं यदि जांच केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है, तो इससे भ्रष्टाचार को अप्रत्यक्ष संरक्षण मिलने की आशंका बनी रहेगी। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। क्या यह मामला केवल दो कर्मचारियों तक सीमित रहेगा या फिर अन्य विभागों में भी चिकित्सा प्रतियुक्ति के नाम पर चल रहे खेल का बड़ा खुलासा होगा। यह आने वाला समय ही तय करेगा।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि का दावा

जन एक्सप्रेस। प्रयागराज

जगदुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एक धर्मगुरु के शिष्य के मुताबिक



मेडिकल जांच में बच्चों का यौन शोषण किया गया है। हालांकि इस बारे में जब पुलिस अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली।

रिपोर्ट विवेचना अधिकारी को सौंपी जाएगी और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके आधार पर ही मुकदमे की आगे की कार्रवाई होगी। नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप से घिरे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में भुगतान संकट गहराया 817 करोड़ से अधिक की एफटीओ राशि लंबित, हजारों मजदूरों की होली पर संकट

जन एक्सप्रेस। संतोष कुमार दीक्षित



नकदी न होने से कपड़े, रंग-गुलाल, मिठाई और रोजगार के सामान की विक्री पर अमर पड़ा है। होली से पहले बाजारों में जो रौनक दिखनी चाहिए, वह इस बार फीकी पड़ती नजर आ रही है। मन्रेगा मजदूरों पर निर्भर हैं। बच्चों की पढ़ाई, राशन, दवाइयों और घरेलू खर्च का आधार यह आय है। होली जैसे बड़े त्योहार से पहले मजदूरों ने मिलना उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। श्रमिक संगठनों ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन देने की तैयारी शुरू कर दी है। चेतावनी दी गई है कि यदि त्योहार से पहले भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

पूर्वांचल और मध्य यूपी में सबसे ज्यादा बकाया

जिलेवार आंकड़े बताते हैं कि कई जिलों में करोड़ों रुपये का भुगतान अटका हुआ है। सबसे अधिक बकाया वाले जिले

- आजमगढ़ 35.10 करोड़ से अधिक
- हरदोई - 33.15 करोड़ से अधिक
- सीतापुर - 32.58 करोड़ से अधिक
- जौनपुर - 31.11 करोड़ से अधिक
- गाजीपुर - 30.68 करोड़ से अधिक

इन जिलों के ग्रामीण इलाकों में मजदूर जनवरी और फरवरी की मजदूरी का इंतजार कर रहे हैं। खेत-खलिहानों और विकास कार्यों में दिन-रात मेहनत करने वाले श्रमिकों का कहना है कि समय पर भुगतान न मिलना उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार है।

योजना का उद्देश्य और मौजूदा चुनौती

मन्रेगा का मूल उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन जब मजदूरी समय पर न मिले, तो योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह रुकने से छोटे दुकानदारों, बीज-खाद विक्रेताओं और दैनिक जरूरत की दुकानों की बिक्री प्रभावित होती है, जिससे समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है।

सरकार से उम्मीद, मजदूरों की मांग

मजदूरों की एक ही मांग है 'हमारी मेहनत की कमाई समय पर हमारे खाते में पहुंच जाए।' अब निगाहें प्रदेश और केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि लंबित 817 करोड़ की राशि का शीघ्र निस्तारण कर होली से पहले भुगतान सुनिश्चित किया जाए। होली उमंग, उत्साह और खुशियों का पर्व है, लेकिन मजदूरों अटकने से हजारों परिवारों की खुशियां अधर में लटकी हैं। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो इस बार रंगों का त्योहार कई घरों में बेरंग रह सकता है।

इन जिलों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर

कुछ जिलों में भुगतान की स्थिति संतोषजनक बताई जा रही है—

- गजियाबाद - 0 बकाया
- बागपत - 2.96 लाख
- कौशांबी - 36.09 लाख
- हापुड़ - 37.24 लाख
- शामली - 81.79 लाख

यहां प्रशासन द्वारा समय पर एफटीओ प्रक्रिया पूरी किए जाने की बात सामने आई है।

क्या है एफटीओ और क्यों अटकता है भुगतान?

एफटीओ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मजदूरों की मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। यह दो स्तरों पर सत्यापन के बाद जारी होती है। विशेषज्ञों के अनुसार भुगतान अटकने के पीछे मुख्य कारण हो सकते हैं—

- तकनीकी त्रुटियां
- बजट आवंटन में देरी
- प्रशासनिक स्तर पर लंबित फाइलें

नयारघाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आगाज, धामी ने किया उद्घाटन, साकारत्मक बाइकिंग रैली आयोजित



जन एक्सप्रेस। सतपुली/कोटद्वार

तीन दिवसीय द्वितीय नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सतपुली के पास स्थित बिलखेत पहुंचे। फेस्टिवल के पहले दिन उद्घाटन समारोह के साथ राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग एक्स्प्रेसी, लैंसडौन से वाया सिसल्डो होते हुए बिलखेत तक 60 किमी की माउंटन बाइकिंग, व्यासघाट में एलिंग और नयार नदी में हंस अस्पताल के पास क्याकिंग प्रतियोगिताएं शुरू हो गईं हैं। फेस्टिवल में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय ग्रामीण भी टैंडम पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, जिप लाइन और ब्रह्मा बिचर का निशुल्क लुफ्त उछ रहें हैं। बिलखेत पैराग्लाइडिंग लैंडिंग स्थल के पास ही इन सारी एक्टिविटीज के सेटअप तैयार किए गए हैं। नयारघाटी

पर्यटन विकास को मिलेगी विशिष्ट पहचान

रैली लैंसडौन के ऐतिहासिक स्थल गांधी चौक से शुरू हुई। उपजिलाधिकारी शालिनी मौर्य ने माउंटन बाइकिंग रैली में प्रतिभाग कर रहे देश के कई प्रांतों से पहुंचे प्रतिभागियों को प्रेरण दिशा कर रवाना किया। एसडीएम ने कहा कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की यह पहल पर्यटन विकास व खेल प्रतिभागियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। एडवेंचर फेस्टिवल के तहत लैंसडौन से वाया सिसल्डो होते हुए बिलखेत तक 60 किमी की माउंटन बाइकिंग शुरू हो गई है। बाइकिंग रैली को लेकर लैंसडौन समेत पूरे रूट पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे।



लखनऊ एक्सप्रेस



एनसीईआरटी विवाद पर शिक्षा मंत्री की सफाई...

एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका से जुड़े कथित विवादाित अघ्याय को लेकर देश में उठे राजनीतिक और न्यायिक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ हुआ उससे उन्हें गहरा दुःख है और सरकार या शिक्षा...

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का हल्लाबोल तीन घंटे तक चला धरना, सिटी स्टेशन सड़क किया जाम

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के खिलाफ बृहस्पतिवार को शिक्षकों ने हल्ला बोला। सिटी स्टेशन की सड़क को जाम किया। शिक्षा भवन परिसर में तीन घंटे से अधिक समय तक धरना दिया। इस दौरान शिक्षकों में काफी रोष नजर आया। शिक्षकों ने चेतावनी दे, नई दिल्ली में मार्च में होने वाले देशव्यापी धरना के दौरान पूरी दिल्ली को जाम किया जाएगा। राजधानी सहित प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता



जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हर तरफ शिक्षकों का विरोध शुरू हुआ। बृहस्पतिवार को इसी सिलसिले में राजधानी के शिक्षकों ने भी एकजुटता का संदेश दिया। शिक्षा भवन परिसर में करीब एक हजार शिक्षक विभाग से आकरिसक छुट्टी लेकर पहुंचे। पूरे परिसर को घेर लिया

और इस दौरान विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी आने-जाने पर कुछ देर तक पाबंदी देखी गई। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुधांशु मोहन ने बताया कि संगठन के आह्वान पर यहाँ सभी शिक्षक संघ के नेता,पदाधिकारी व विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शामिल हुए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों की टीईटी की अनिवार्यता का आदेश दिया। जो किसी भी स्तर पर सही नहीं है। कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षक मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री

के नाम जिला प्रशासन को जापन दिया गया है। टीईटी अनिवार्यता के आदेश को खत्म करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार-2009 के तहत जुलाई 2011 में लागू अधिनियम के अनुसार, शिक्षकों की टीईटी अनिवार्यता है जबकि उससे पहले वाले शिक्षकों के लिए नहीं है। कोर्ट ने अधिनियम को नजरअंदाज करने हुए सभी के लिए यह व्यवस्था लागू कर दी। जो कि शिक्षकों के साथ पूरी तरह से गलत है। इसी सिलसिले में बृहस्पतिवार को धरना दिया गया ताकि टीईटी अनिवार्यता से छूट मिले।

गौरव का क्षण: लता सिंह ने एओआर परीक्षा में रचा इतिहास

जन एक्सप्रेस | लखनऊ



पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के परिवार से एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। उनकी सुपुत्री एवं समाजसेवी सुश्री लता सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे समाज का मान बढ़ाया है। Supreme Court of India द्वारा आयोजित एओआर परीक्षा देश की सबसे कठिन और सम्मानित विधिक परीक्षाओं में गिनी जाती है। इस वर्ष लगभग 5000 अधिकतारों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से मात्र 207 अर्थव्यथी ही सफलता प्राप्त कर सके। ऐसे

प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफलता हासिल करना असाधारण परिश्रम, गहन विधिक ज्ञान और अदम्य आत्मविश्वास का प्रमाण माना जाता है। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि एक प्रेरक संदेश भी है-कि स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़

संकल्प के साथ कोई भी शिखर दूर नहीं। जब परिवार में संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना रची-बसी हो, तब उपलब्धियां इतिहास बन जाती हैं। उल्लेखनीय है कि परिवार की दूसरी संतान भारतीय पुलिस सेवा में चयनित होकर देशसेवा में योगदान दे रही है। एक ओर सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में मान्यता और दूसरी ओर प्रशासनिक सेवा में योगदान-यह उपलब्धि परिवार की सोच, परिवार और मूल्यों की सफलता को दर्शाती है। सुश्री लता सिंह की इस सफलता पर समाजसेवी आशीष रंजन सिंह एवं डॉ. राजेश वर्मा ने शुभकामनाएं देते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया।

यूपी-यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर एमओयू जापान में प्रशिक्षण लेंगे छात्र



जन एक्सप्रेस | लखनऊ

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान दौर पर हैं। गुरुवार को यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर एमओयू हुआ है। इसके तहत भारतीय छात्रों को जापान में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। सीएम ने यामानाशी में आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में हिस्सा लिया। साथ ही यूपी की नई विकास नीति और निवेश संभावनाओं को वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि यूपी ने शासन की कार्यशैली को रिफ़ैक्टिव से बदलकर प्रोएक्टिव बनाया है। यही परिवर्तन आज प्रदेश की तेज आर्थिक प्रगति का आधार बना है। उधर, यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में कई जी2जी (गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट) और जी2बी (गवर्नमेंट टू बिजनेस) स्तर की बैठकों

में भाग लिया है। वहां भारतीय दूतावास के सहयोग से जापानी उद्योग समूहों से व्यापक संवाद हुआ।

ग्रीन हाइड्रोजन पर ऐतिहासिक समझौता

इस मौके पर सीएम ने आगे कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को प्रदेश की इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

तकनीक और भविष्य के क्षेत्रों पर जोर

सीएम ने रोबोटिक्स को भविष्य की प्रमुख तकनीक बताया। कहा कि, यूपी सरकार ने बजट में रोबोटिक्स के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सिलेंस

उत्तर प्रदेश की ताकत को दुनिया के सामने रखा

सीएम ने कहा कि लगभग 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहां प्रकृति की विशेष कृपा है। भारत की सबसे उर्वर भूमि, सर्वाधिक जल संसाधन, विशाल मानव संसाधन और आध्यात्मिक-सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश को विशेष पहचान देते हैं। पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तथा अर्थव्यवस्था तीन गुना करने में सफलता मिली है।

'रिफ़ैक्टिव से प्रोएक्टिव' मॉडल बना विकास का आधार

सीएम ने कहा कि पहले समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था थी। अब प्रदेश ने प्रोएक्टिव गवर्नंस मॉडल अपनाया है। निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को सुविधा देने, नई तकनीक अपनाने और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार पहल कर रही है। इसी सोच के साथ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान की यात्रा पर आया है। ताकि, संभावनाओं को अवसर में बदला जा सके।

यामानाशी से गहरे होते संबंध

सीएम ने यामानाशी प्रांत के राज्यपाल एवं उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। मौजूद इंडस्ट्री लीडर्स तथा भारतीय समुदाय के लोगों का भी स्वागत किया। कहा कि दिसंबर 2024 में यामानाशी के राज्यपाल उत्तर प्रदेश आए थे। उसके बाद दोनों सरकारों के बीच निरंतर संवाद, फॉलोअप तथा प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान से यह सहयोग नई दिशा में आगे बढ़ा। बिजनेस डेवेलोपमेंट के अध्ययन और रिपोर्ट के बाद आज राज्यपाल के आमंत्रण पर प्रतिनिधिमंडल यामानाशी पहुंचा है।

स्थापित करने की व्यवस्था की है। हमें विश्वास है कि यामानाशी से सहयोग भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा तकनीक को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर यामानाशी प्रांत के राज्यपाल कोटारो नागासाकी, उपराज्यपाल जुनिचि

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने की जनसुनवाई

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपने आवास पर जनसुनवाई कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। विद्युत कनेक्शन से संबंधित प्रकरण, विद्युत बिल में त्रुटि सुधार, सीवर लाइन की समस्याएं, नवीन निर्माण कार्यों की स्वीकृति, क्षतिपूर्ति भुगतान तथा स्थानीय जनसमस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। श्री शर्मा ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए तथा निस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जनसुनवाई केवल औपचारिकता न होकर परिणामोन्मुखी होनी चाहिए, जिससे लोगों को वास्तविक राहत मिल सके। विद्युत एवं नगर विकास से जुड़े मामलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर अनावश्यक विलंब न किया जाए।

पहले कब्जा, फिर कारोबार... बाद में कार्रवाई

सरकारी चबूतरे पर खड़ी हो गई बहुमंजिला इमारत, दुकान भी चलने लगी, अब जागा एलडीए



जन एक्सप्रेस | लखनऊ

राजधानी में अवैध निर्माण का खेल अब खुलेआम सरकारी जमीन तक पहुंच चुका है। बरिगंवा स्थित बड़े बाबा हनुमान मंदिर के पास नगर निगम के सरकारी चबूतरे पर ही दो मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई और उसमें 'श्री राज वेज कबाब' नाम से व्यावसायिक दुकान भी संचालित होने लगी। हैरानी की बात यह है कि पूरा निर्माण और कारोबार शुरू होने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) हरकत में आया है। आलमनगर वार्ड निवासी नीरज कुमार यादव की शिकायत पर

आईजीआरएस पोर्टल के जरिए मामला सामने आया। शिकायत संख्या 40015726017053 पर प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने 24 फरवरी 2026 को मौके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अवर अभियंता विभोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट में स्पष्ट पाया गया कि सरकारी भूमि पर भूतल और प्रथम तल तक अवैध निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। यानी पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और फिर उसे कमाई का साधन बना दिया गया। एलडीए ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत कार्रवाई

सिस्टम पर बड़े सवाल

- सरकारी चबूतरे पर निर्माण अधिकारियों की नजर से कैसे बच गया?
 - दो मंजिला ढांचा तैयार होने तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
 - क्या बिना विभागीय संरक्षण के इतना बड़ा निर्माण संभव है?
- राजधानी में लगातार सामने आ रहे अवैध निर्माण के मामलों के बीच यह प्रकरण प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जो कब्जा और कारोबार होने तक खामोश रहती है और शिकायत आने पर ही सक्रिय दिखाई देती है।

शुरू करते हुए ऑनलाइन वाद संख्या 4/00007147 (दिनांक 24.02.2026) दर्ज कर प्रकरण सक्षम प्राधिकरण को भेज दिया है। हालांकि शिकायतकर्ता जांच से संतुष्ट नहीं हैं। उनका आरोप है कि जब निर्माण चरणबद्ध तरीके से खड़ा हो रहा था, तब जिम्मेदार विभागों ने कार्रवाई क्यों नहीं की।

यूपी को फाइलेरिया मुक्त बनाने का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे: डॉ पिंकी जोवल

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

यूपी को फाइलेरिया हाथी पांव एवं पुरुषों में हाइड्रोसील से मुक्त किए जाने हेतु फाइलेरिया उन्मूलन अभियान 10 से 28 फरवरी तक 21 जनपदों के 64 प्लानिंग यूनिट में संचालित है। अभियान के महत्व के दृष्टिगत प्रदेश स्तर पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इसका नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ पिंकी जोवल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें उन 15 प्लानिंग यूनिट में अभियान की

प्रगति की समीक्षा की गई, जहां लक्ष्य के अनुरूप अब तक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ ही शाहजहांपुर उन्नाव, बाराबंकी एवं बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक एवं संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ पिंकी जोवल ने अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। फाइलेरिया उन्मूलन भारत सरकार के साथ ही प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं

में एक है और प्रदेश सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।मिशन निदेशक ने कहा कि जिन क्षेत्रों में दवा सेवन की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहाँ विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य को पूरा किया जाए। रमजान के महीने के दृष्टिगत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा सायंकालीन ध्रमण, रोजा इफ्तार उपरांत किया जाए। उन्होंने दवा खाने से इन्कार करने वाले लाभार्थियों को 'इस बीमारी के लाइलाज होने' व 'दवा सेवन ही एकमात्र बचाव' के महत्व को समझाते हुए उन्हें दवा का सेवन कराया जाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य

लाभार्थियों की शत-प्रतिशत लाइन लिस्टिंग सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। आशा कार्यकर्ताओं एवं फ़्रंटलाइन स्वास्थ्य टीमों की सक्रिय एवं सुनियोजित भागीदारी इस अभियान की सफलता की आधारशिला है। उन्होंने ड्यू एडमिनिस्ट्रेटर्स की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने, लाभार्थियों को दवा खिलाते समय उचित प्रोटोकॉल का पालन करने और किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने की भी बात कही।डॉ जोवल ने कहा कि अभियान की समाप्ति तक 28 फरवरी तक सभी जनपद अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें।

बसपा एमएलए और करीबियों के घर से 10 करोड़ कैश बरामद, ऑफिस और अन्य जगहों पर कार्रवाई जारी

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

राजधानी लखनऊ में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों के घर पर बुधवार से जारी आयकर टीम का छपा गुरुवार को समाप्त हो गया। उनके घर से 10 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। अभी उनके ऑफिस और अन्य स्थानों पर कार्रवाई जारी है। विपुलखंड स्थित उनके आवास पर कार्रवाई पूरी हो गई है।

जार्न पूरा मामला

बलिया की रसड़ विधानसभा सीट से एकमात्र बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर बुधवार हसन रोड पर करीबी टेक्रेडर फैजी के ठिकानों को खंगला। इसके अलावा सोनभद्र में साईं राम इंटरप्राइजेज कंपनी के नाम से खनन का कारोबार करने वाले उमाशंकर सिंह के करीबी सीबी गुप्त समेत कई खनन कारोबारियों के ठिकानों को खंगला जा रहा है। आयकर विभाग ने सुबह 11 बजे सभी ठिकानों पर एक साथ छपा मारा था, जिसके बाद टेक्स चोरी और बेनामी



गोमतीनगर में विपुल खंड स्थित उमाशंकर सिंह के आवास, उनकी कंपनी छत्रशक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी के कारपोरेट ऑफिस और वजीर हसन रोड पर करीबी टेक्रेडर फैजी के ठिकानों को खंगला। इसके अलावा सोनभद्र में साईं राम इंटरप्राइजेज कंपनी के नाम से खनन का कारोबार करने वाले उमाशंकर सिंह के करीबी सीबी गुप्त समेत कई खनन कारोबारियों के ठिकानों को खंगला जा रहा है। आयकर विभाग ने सुबह 11 बजे सभी ठिकानों पर एक साथ छपा मारा था, जिसके बाद टेक्स चोरी और बेनामी

संपत्तियों से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। खनन घोटाले में आया था नाम उमाशंकर सिंह छत्रशक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी और साईं राम इंटरप्राइजेज के नाम से सड़क और खनन से जुड़े कार्य करते हैं। बीते वर्ष सीएजी (कैंग) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सोनभद्र में अवैध खनन कार्यों से करीब 60 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि हुई थी। माना जा रहा है कि सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद ही उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों

बराती बनकर पहुंचे थे अधिकारी

बलिया में विधायक उमाशंकर के आवास पर छपा मारना आयकर विभाग के लिए आसान नहीं था। ऐसे में टीम सरकारी गाड़ियों के बजाय बरातियों के अंदाज में पहुंची। वाहनों पर महेंद्र कुमार संग संगीता कुमारी नाम के शादी वाले स्टैकर लगा दिए गए, ताकि किसी को शक न हो। इसी रणनीति की आड़ में अधिकारी बिना शोर-शराबे के सीधे आवास तक पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी।

कई ब्यूरोक्रेट निशाने पर

आयकर छापे में सोनभद्र और मिर्जापुर में बीते कुछ वर्षों के दौरान हुए अवैध खनन से जुड़े अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसमें कई अधिकारियों के नाम और उनको दी जाने वाली रकम का जिक्र है। आयकर विभाग को शक है कि खनन कारोबार में कई ब्यूरोक्रेट्स की काली कमाई का निवेश किया गया है, जिसके सुराग जुटाए जा रहे हैं।

के ठिकानों को खंगला गया है। प्रोत्साहन मिलेगा। एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर, औद्योगिक पार्क और निवेश क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निवेशकों को भूमि, परिवहन और बाजार तक त्वरित पहुंच उपलब्ध हो सके।लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार से प्रदेश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। निर्यात उन्मुख उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। बुदेलखंड और पूर्वांचल जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने से क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी। एक्सप्रेस-वे आधारित विकास मॉडल से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार सृजन में भी बढ़ोतरी होगी।

राजधानी में एफएसडीए की सख्ती का असर नोटिस मिलते ही ढाबे में 'ग्यारह दिन में सुधार', अब मौके पर जांच की मांग

गंभीर खामियां मिलने पर जारी हुआ नोटिस, संचालक ने सुधार का दावा किया, भौतिक सत्यापन पर टिकी विभागीय कार्रवाई

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई में राजधानी के खाद्य प्रतिष्ठानों में हलचल तेज कर दी है। आलमनगर क्षेत्र स्थित एक ढाबे में निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं नोटिस के बाद विभाग द्वारा इम्प्यूमेंट नोटिस जारी किया गया। नोटिस मिलते ही संचालक ने व्यवस्थाएं सुधारने का दावा करते हुए अब अधिकारियों से भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है।



खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई

● पत्रांक 507/एफएसडीए/नोटिस/2026 जारी, 15 दिन में सुधार के निर्देश
● नोटिस के बाद सुधार का दावा
● संचालक धर्मपाल यादव ने विभाग को भेजा लिखित प्रत्युत्तर
● सभी कमियां समय सीमा में दूर करने का दावा
● नियमित साफ-सफाई और बर्तनों का सेनेटाइजेशन शुरू
● अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था लागू करने की जानकारी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई

लखनऊ के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा सुशे कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता परक योजनान्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 28 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लखनऊ के मजरा गनियार ग्राम पंचायत भौदई ब्लॉक मोहनलालगंज में पं दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेला,शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें जनपद के पशुपालकों को विभाग द्वारा विभिन्न सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।डा सुशे कुमार ने बताया कि शिविर में रोगी पशुओं का अति विशिष्ट उपचार एवं औषधि वितरण, रोग प्रस्त पशुओं की अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा जांच, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं बॉक्सेप समस्या का निवारण, पशुओं की लघु शल्य चिकित्सा, निःशुल्क पशु टीकाकरण, पशुपालकों को पशुओं के पशुधन बीमा की सुविधा तथा पशुपालकों को पशुओं की उच्च तकनीकी वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी जायेगी।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई

ढाबों पर भी होगी सख्त जांच? FSDA अभियान से बढ़ी खाद्य कारोबारियों की चिंता राजधानी में FSDA की सक्रियता ने संकेत दे दिया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों से समझौता अब आसान नहीं होगा। निरीक्षण अभियान आगे और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

यूजीसी बिल के समर्थन में अपनी जनता पार्टी का प्रदर्शन

जन एक्सप्रेस | अम्बेडकरनगर

जनपद में यूजीसी बिल के समर्थन में अपनी जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के निकट जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर यूजीसी बिल लागू कराने की मांग की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के निदेशानुसार आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और संविधान सम्मत बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि एससी,



एसटी, ओबीसी एवं इंडब्युएस वर्ग के छात्रों के साथ हो रहे कथित जातीय अपमान और भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से यूजीसी एक्ट लागू किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने से सामाजिक न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि केंद्र सरकार इस मामले में आवश्यक हस्तक्षेप कर यूजीसी बिल को प्रभावी रूप से लागू कराए, ताकि वंचित

वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर मिल सके। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। इस अवसर पर रजनीश मौर्य (प्रदेश महासचिव), विजय कुमार मौर्य (जिला अध्यक्ष), अमित मौर्य, (जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा), जितेंद्र मौर्य, उदय राज पटेल, शैलेश विजय कुमार, दिलीप कुमार, वैभव मौर्य, धर्मेन्द्र कुमार, बबलू मौर्य, रामप्रकाश चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन सौंपने के उपरांत पार्टी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।

दुकानदारों की समस्या को लेकर सपा मजदूर सभा ने सौंपा ज्ञापन

जन एक्सप्रेस | बलरामपुर

जनपद बलरामपुर में समाजवादी मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार श्रीवास्तव ने आर्थिक रूप से कमजोर एवं छोटे दुकानदारों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।



सपा मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव द्वारा 26 फरवरी को दिए गए ज्ञापन में नगर क्षेत्र में आजीविका चलाने वाले दुकानदारों की कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनके हित में ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि कई छोटे दुकानदार आर्थिक तंगी के कारण अपनी दुकानों का संचालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे दुकानदारों को राहत देने के लिए उनकी आय, परिस्थिति एवं जरूरत के आधार पर उचित सहायता प्रदान की जाए। साथ ही जिन दुकानदारों की दुकानों का पुनर्बांसा या स्थान परिवर्तन प्रस्तावित है,

उनके लिए वैकल्पिक स्थान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उनकी रोजी-रोटी प्रभावित न हो। उन्होंने मांग किया है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले संबंधित दुकानदारों को नोटिस देकर संवाद स्थापित किया जाए और उनकी समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण से समाधान निकाला जाए। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि विकास कार्यों के साथ-साथ गरीब एवं मेहनतकश व्यापारियों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी परिवार की आजीविका पर संकट न आए। आपको बताते चलें कि आदर्श नगर पालिका परिषद द्वारा नगर की पुरानी दुकानों को तोड़कर नई दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। नई दुकानों के आवंटन में पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता तो दी जा रही है, परंतु धरोहर राशि ज्यादा होने के कारण अधिकतर दुकानदारों के लिए जमा कर पाना संभव नहीं है।

छतरी लगाकर सिम बेचने वालों पर उठे सवाल, पुलिस की भूमिका पर भी चर्चा

जन एक्सप्रेस/रायबरेली।

शहर में अतिक्रमण कर सड़क किनारे अस्थायी रूप से सिम बेचने वालों को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला डिट्री कॉलेज चौराहे के पास का बताया जा रहा है, जहां फुटपाथ पर छतरी लगाकर मोबाइल सिम बिक्री का काम किए जाने की शिकायत सामने आई है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जहां एक ओर शहर में अन्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है, वहीं दूसरी ओर यहां खुलेआम फुटपाथ बेकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। लोगों का कहना है कि इससे पैदल राहगीरों को आने-जाने में दिक्कत होती है और यातायात भी प्रभावित होता है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सिम से संबंधित समस्या लेकर पहुंचे ग्राहकों को उचित जानकारी या व्यवहार नहीं मिला। शिकायत करने पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भी संतोषजनक सहयोग न मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि फुटपाथ पर लगाए गए इन अस्थायी स्टालों से व्यवस्था प्रभावित हो रही है और प्रशासन को इस पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। वहीं, पुलिस या संबंधित विभाग की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। शहरवासियों का मानना है कि यदि फुटपाथ सार्वजनिक उपयोग के लिए है, तो वहां इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति और निगरानी को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को असुविधा न हो।



शिक्षक फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले शिक्षक संघों ने सौंपा ज्ञापन

जन एक्सप्रेस | बलरामपुर

जनपद बलरामपुर में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ व जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने गुरुवार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को टी.ई.टी. की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। जानकारी के अनुसार 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ व जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, 27 जुलाई, 2011 से लागू किया गया है। अधिनियम के अनुसार अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से अथवा उसके उपरान्त नियुक्त होने वाले शिक्षकों को शिक्षक पाठ्य परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है, जबकि उसके पूर्व में नियुक्त सभी शिक्षकों को टी.ई.टी. की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 01 सितम्बर, 2025 को दिए गए



निर्णय के द्वारा देश के सभी राज्यों में अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को भी सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति हेतु टी.ई.टी. उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है, जोकि पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के साथ सरासर अन्याय है। फलस्वरूप देश भर के शिक्षक टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आन्दोलनरत रहकर भारत सरकार से अपनी मांगों के सम्बन्ध में अत्यादेश लाकर आर.टी.ई. से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टी.ई.टी. से छूट देने की अपील कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में

जनपद के सभी शिक्षकों ने 26 फरवरी, 2026 को अपराह्न से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया तथा जिलाधिकारी के माध्यम से आपको ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का सजान लेते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को टी.ई.टी. से छूट प्रदान करने हेतु अत्यादेश लाकर संसद द्वारा कानून शरित करने की कृपा करें। ज्ञापन देते समय सभी सांझों के जिला

अध्यक्ष, महामंत्री व अन्य पदाधिकारियों सहित ज्ञान सागर पाठक, अवधेश कुमार श्रीवास्तव, कमरुद्दीन अंसारी, अरुण कुमार यादव, पंकज पांडेय, शिवकुमार सोनी, आलोक मणि पांडे, विकास, पंकज सिंह, बुद्धि सागर शुक्ला, राकेश कुमार मिश्रा, सत्यप्रकाश पाठक, विपिन कुमार पाण्डेय, नीरज सिंह, बेद प्रकाश पाण्डेय, राजकुमार वर्मा, दिनेश कुमार वर्मा, कुसुम कुमारी, राजेश कुमार तथा अशोक कुमार सहित सैकड़ों शिक्षक सम्मिलित हुए।

रफ्तार का कहर: भीषण सड़क हादसा, तीन की दर्दनाक मौत



रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में लखनऊ-प्रयागराज मार्ग पर महोलिया गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में जगतपुर थाना क्षेत्र के संदीप सिंह, धनंजय सिंह और आशुतोष मौर्य शामिल हैं। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

एनटीपीसी से निकले गए श्रमिकों का प्रदर्शन, पुनः नियुक्ति की मांग

जन एक्सप्रेस | अम्बेडकरनगर

जनपद के टांडा स्थित एनटीपीसी में कार्यरत निर्माण श्रमिकों को कार्य से हटाए जाने का मामला सामने आया है। प्रभावित श्रमिकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और दोबारा भर्ती की मांग उठाई। श्रमिकों का आरोप है कि वे पिछले 20 से 25 वर्षों से पावर प्लांट में कार्यरत थे, लेकिन उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के मौखिक रूप से काम पर आने से मना कर दिया गया। उनका कहना है कि इस निर्णय से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने एनटीपीसी के मानव संसाधन विभाग के एक अधिकारी पर मनमानी का आरोप



लगाते हुए कहा कि पुराने श्रमिकों को हटाकर नए लोगों की भर्ती की जा रही है। इस संबंध में श्रमिकों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूनियन नेता अयोध्या प्रसाद पटेल ने बताया कि श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला और ज्ञापन सौंपकर पुनः नियुक्ति तथा

पूरे प्रकरण की जांच की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आगे आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इस मामले में एनटीपीसी मानव संसाधन प्रबंधन अनुराग सिन्हा से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठया गया।

जिला कारागार का डीएम, एसपी और मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण

जन एक्सप्रेस | बलरामपुर

गुरुवार को डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुज कुमार पाण्डेय द्वारा जिला कारागार का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कारागार के विभिन्न बंकरों, चिकित्सालय, पुरुष एवं महिला बंकर सहित अन्य व्यवस्थाओं का स्थलीय जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अस्पृश्यक बैरक में निरूद्ध बंदियों से संवाद कर उनकी कुशलक्षेम जानी तथा अस्पताल बैरक में भर्ती बंदियों से मिलकर उपचार एवं देखभाल की स्थिति की जानकारी ली। अस्पताल परिसर की साफ-सफाई एवं बीमार बंदियों की उचित देखभाल को देखकर अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया। कारागार अधीक्षक श्री विजय कुमार शुक्ल ने बताया कि जेल चिकित्सालय में एक चिकित्सक एवं एक फार्मासिस्ट तैनात हैं तथा 20 बेड की व्यवस्था उपलब्ध है। बंदियों के उपचार हेतु आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।



इसके पश्चात अधिकारियों ने परेड के दौरान बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी तथा महिला बैरक का भी निरीक्षण किया। महिला बंदियों से उनके मुकदमों की जानकारी लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को दी जा रही शिक्षा, पोषण एवं देखभाल संबंधी सुविधाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को भी समीक्षा की। कारागार परिसर की साफ-सफाई, सुव्यवस्थित व्यवस्था एवं हरियाली को भी अधिकारियों ने सराहा। इस अवसर पर कारागार चिकित्साधिकारी डॉ. रलेश वर्मा, उपकारापाल शरदा देवी, उपकारापाल राम प्रवेश, उपकारापाल अभय कुमार यादव, मुख्य चीफ कामता प्रसाद भार्गव सहित अन्य कारागार कर्मी उपस्थित रहे।

वृहद रोजगार मेला 27 फरवरी को

रायबरेली। जिला सेवायोजन अधिकारी तनुजा यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार के तहत वृहद रोजगार मेलों का आयोजन कर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला सेवायोजन कार्यालय रायबरेली द्वारा 27 फरवरी को कर्मयोगी डिट्री कालेज, मुलिहामऊ, रायबरेली के परिसर में एक वृहद रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें रायबरेली सहित देश एवं प्रदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों और नियोजकों द्वारा नॉन टेक्निकल एवं टेक्निकल दोनों प्रकार के पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इस रोजगार मेले में बहुत सी कंपनियों द्वारा चयन किया जाएगा। इस मेले में हाईस्कूल, इण्टर, स्नातक, पारस्नातक, आईटीआई, बीटेक, आईटी मैनुफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, तकनीकी और गैर तकनीकी सभी क्षेत्र की कंपनियां उपलब्ध रहेंगी। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि मेले में समस्त योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु लगभग 2000 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध हैं। वृहद रोजगार मेले में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के समस्त पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। मेले में कंपनियों द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क होगी। मेले में शामिल होने वाली बड़ी कंपनियां- पेरिग्रीन गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में सिविलीटी गार्ड-200, वेलसुन लिमिटेड में मशीन ऑपरेटर-120, महादेव हनुमान विजय प्लेसमेंट सर्विस द्वारा टाटा मोटर्स एवं एम0आर0एफ0 यजकी लिमिटेड-650, लुमेक्स मग्रोह एलाइड टेक्नोलॉजीस लिमिटेड में असेम्बली ऑपरेटर-50, उमोजा मार्केट प्लेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिलायंस एवं जैमेटो यूनो मिंडा कंपनी-580 इत्यादि।

भूली नगर-थौरी सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप

जन एक्सप्रेस/अमेठी। जगदीशपुर क्षेत्र में भूली नगर से थौरी तक बन रही सड़क के निर्माण कार्य को लेकर गुरुवार को विवाद खड़ा हो गया। करीब 50 लाख रुपये की लागत से बन रही सड़क में गुणवत्ता संबंधी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सदस्य अमय सिंह ग्रामीणों के साथ निर्माण स्थल पर पहुंच गए। मौके पर ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए सड़क की जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में मानक के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि सड़क की परत पतली है और खटिया सामग्री लगने से इसकी मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे और निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की। जिला पंचायत सदस्य अमय सिंह ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकारी धन से बन रही सड़क में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्य को मानकों के अनुसार कराया जाए। उन्होंने निर्माण कार्य की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सड़क की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया तो वे धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। फिनाइल मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी और यदि कहीं अनियमितता पाई गई तो संबंधित ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई

105 लीटर कच्ची शराब बरामद, तीन अभियोग दर्ज

जन एक्सप्रेस | अमेठी

अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग ने गुरुवार को कई गांवों में आकस्मिक छापेमारी कर कार्रवाई की। टीम ने ग्राम चतुरीपुर, बेनीपुर, हारीमऊ और मजीठा में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र-1 गौरीगंज में थाना गौरीगंज क्षेत्र से कुल 105 लीटर प्रयुक्त करीब 350 किलोग्राम महुआ लहन को नष्ट कराया गया। इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत तीन अभियोग दर्ज किए गए हैं। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी के साथ ही ग्रामीणों को अवैध शराब के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक

किया। विभाग ने लोगों से अपील की कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री या परिवहन की सूचना तत्काल टोल फ्री नंबर या संबंधित आबकारी निरीक्षक को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा टीम ने अधिकृत आबकारी दुकानों का भी निरीक्षण कर बिक्री व्यवस्था की जांच की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध शराब के कारोबार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 गौरीगंज के नेतृत्व में आबकारी स्टाफ अमित कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, पुष्पेंद्र कुमार तथा महिला आबकारी सिपाही प्रीती पाल शामिल रहीं। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

धरना-प्रदर्शन कर शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता का किया विरोध

जन एक्सप्रेस | रायबरेली

टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) के बैनर तले टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में जनपद के शिक्षकों ने आज विकास भवन परिसर में समर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में विशाल धरना-प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, शाखा-रायबरेली के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि शिक्षकों की पीड़ा के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार की ओर से शिक्षकों की संवेदन में एक शब्द नहीं कहा गया, जिससे शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, शाखा-रायबरेली के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि शिक्षकों की पीड़ा के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार की ओर से शिक्षकों की संवेदन में एक शब्द नहीं कहा गया, जिससे शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, शाखा-रायबरेली के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि शिक्षकों की पीड़ा के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार की ओर से शिक्षकों की संवेदन में एक शब्द नहीं कहा गया, जिससे शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है।



अध्यक्ष गीता त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो शिक्षक दिवह कूच करने के लिए बाध्य होंगे। जिला मंत्री मुकेश चंद्र द्विवेदी एवं विद्या राम सोनकर ने कहा कि शिक्षक हितों की रक्षा के लिए टीएफआई का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन जनपदीय संयुक्त मंत्री डा. चंद्र मणि बाजपेई ने किया। धरना-प्रदर्शन में जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से आए जटाशंकर बाजपेई, राकेश द्विवेदी, अरविंद द्विवेदी, राजेश यादव, सुधीर सिंह, सुरेश सिंह,

त्रिवेदी, नीरज शुक्ल, सुधीर द्विवेदी, पूनम सिंह, रेणु शुक्ल, प्रतिमा, साधना, दीपशिखा, मंजुलता, प्रीति, रुचि, इसमत बानो, ललिता, कल्पना, मो. सगीर, दर्शन लाल लोधी, धर्मेन्द्र सिंह, अजय मिश्र, रमाशंकर, अरुण कुमार, ब्रमप्रकाश, रामेंद्र यादव, नीरज सोनी, अरविंद कुमार, अभिषेक मिश्रा, दुर्गेश मिश्रा, सर्वेश शुक्ल, शशिकांत, शैलेंद्र सिंह, प्रमोद शुक्ल, राकेश शुक्ल, संतोष, इमरान, पारुल कुमार, विवेक, कीर्ति मनोहर, अवध किशोर, बलराज सिंह, पीपूष, अमित गुप्त, सूरज यादव, अशोक पाल, मुशा लाल, राजेंद्र यादव, आलोक, शीतला प्रसाद, राजेश त्रिवेदी, अशोक यादव, मंजुलता अवस्थी, बृजेश कुमार, राम कुमार सिंह, सर्वेश कुमार, दीपक द्विवेदी, अमरेंद्र यादव, आशीष त्रिपाठी, अता मोहम्मद, राम निवेश, बृजेश पांडे, मोनू, संघर्ष पटेल, मयंक सहित हजारों शिक्षक उपस्थित रहे। धरना-प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, किंतु शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि मांगें न माने जाने की स्थिति में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

अब आएगा मजा... बॉलीवुड के खिलाड़ी और भोजपुरी स्टार

अक्षरा सिंह

वया करने वाले हैं? फोटो ने मचाई हलचल

भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं, कभी अपने गानों को लेकर तो कभी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर. हाल ही में अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी, जो आते ही चारों तरफ वायरल हो गई. दरअसल, अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार के साथ एक फोटो पोस्ट की, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. इतना ही नहीं, इस तस्वीर पर अक्षरा सिंह ने जो कैप्शन दिया, उसने लोगों में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी.

अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की टॉपी हीरोइनों में से एक हैं. वो सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. हाल ही में उनकी अक्षय कुमार संग फोटो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. इस फोटो पर लोग अलग-अलग रिएक्शंस दे रहे हैं. साथ ही, इसे देखकर लोग कह रहे हैं कि शायद दोनों की प्रोजेक्ट पर साथ काम करने वाले हैं.

अक्षरा सिंह की अक्षय कुमार संग पोस्ट

सोमवार, 23 फरवरी को अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्षय कुमार के साथ एक फोटो पोस्ट की. इस फोटो को पोस्ट करते हुए



कुछ बड़ा आने वाला है...

अक्षरा सिंह ने लिखा, जब खिलाड़ी मृगनैनी से मिलता है और कहानी अभी बाकी है. साथ ही, इस पोस्ट में अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार को टैग भी किया. इस कैप्शन को पढ़कर लोग यही मान रहे हैं कि दोनों जल्द ही किसी गाने या फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं. हालांकि, ये प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, इस बारे में अक्षरा सिंह ने कोई हिंट नहीं दिया है.

सोमवार, 23 फरवरी को अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्षय कुमार के साथ एक फोटो पोस्ट की. इस फोटो को पोस्ट करते हुए अक्षरा सिंह ने लिखा, जब खिलाड़ी मृगनैनी से मिलता है और कहानी अभी बाकी है. साथ ही, इस पोस्ट में अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार को टैग भी किया. इस कैप्शन को पढ़कर लोग यही मान रहे हैं कि दोनों जल्द ही किसी गाने या फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं. हालांकि, ये प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, इस बारे में अक्षरा सिंह ने कोई हिंट नहीं दिया है.

शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान पर अड़ी

जीनत अमान

बोलीं- मेरा पहले भी यही नजरिया था

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान अपने बेबाक बयान को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं. हर मुद्दे पर वो खुलकर बात करती हैं, फिर चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, शादी हो, या फिर रिलेशनशिप. बीते काफी वक्त पहले जीनत अमान ने लिव इन रिलेशनशिप पर बात की थी, जिसपर काफी विवाद भी हुआ था. इसी के बाद एक्ट्रेस फिर एक पोस्ट कर अपने लिव इन रिलेशनशिप वाले

बयान पर अडिग हैं. जीनत अमान ने एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए कहा कि 1990 के दशक से उनकी यही राय बना हुई, जिसपर वो आज भी विश्वास करती हैं. जीनत अमान ने अपने सोशल मीडिया पर 1990 के पुराने इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर करते हुए अपने रुख को दोहराया है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए जीनत अमान ने लंबा चौड़ा सा कैप्शन भी लिखा, जिसमें वो कहती हुईं नजर आईं कि वो कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहती हैं, बल्कि वो वही सच बता रही हैं जो उन्होंने समझा है.

अपने बयान पर अड़ी जीनत अमान

जीनत ने सिमी गरेवाल के साथ अपने 1999 के इंटरव्यू का एक शोर्बेक क्लिप पोस्ट किया. इसके कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, याद है मैंने कुछ महीने पहले लिव-इन रिलेशनशिप पर अपनी राय पोस्ट की थी? इससे मेरे कुछ साथियों के

बीच काफी हंगामा हुआ था और पारंपरिक मूल्यों का अपमान करने के हमेशा के आरोप भी लगे थे. खैर, ये रहा अतीत की एक झलक - मेरी युवावस्था का वही नजरिया, जिसमें मैं ठीक यही बात कर रही थी. मैं सच में कोई विवाद नहीं खड़ा कर रही हूँ, बल्कि बस अपने एक्सपीरियंस से जो सच मैंने समझा है, उसे बता रही हूँ.

अपना नजरिया समझाते हुए जीनत ने लिखा, मेरे हिसाब से, किसी रिश्ते को उसमें शामिल दो लोगों के लिए पवित्र मानना ज्यादा जरूरी है. बजाय इसके कि शादी के जरिए समाज के लिए उसे पवित्र किया जाए. ये सोचना कि आप बिना सरकार या धर्म की मंजूरी के एक अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते. सच कहूँ तो, उतना ही मजेदार है जितना ये मानना कि शादी किसी नाखुश रिश्ते को जादुई तरीके से ठीक कर सकती है.

मैं उम्मीदों को समझती हूँ...

जीनत अमान लिखती हैं, मैं समाज की उम्मीदों को समझती हूँ. लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि आज ज्यादा से ज्यादा युवा बराबरी के तौर पर रिश्तों में आ रहे हैं - ऐसे बनाने, रिश्ते बनाने, सुरक्षा पाने, माता-पिता को खुश करने या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं - बल्कि इंसानी रिश्ते की खूबसूरती का अनुभव करने के लिए. एक अच्छे रिश्ते की नींव उसका सरकारी स्टेटस नहीं है.



अपनी बात पर अड़ी जीनत अमान

‘वो मुझे तिरछी नजर से...’ जब जैकी श्राफ से घबराई माधुरी दीक्षित, ऐसी थी दोनों की पहली मुलाकात



बीत गए 40 साल

देश के दिग्गज कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों नेटफ्लिक्स पर अपने शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन से फैंस का दिल जीत रहे हैं. कपिल के शो में एक के बाद एक बॉलीवुड सेलेब्स शिरकत करते हैं. अब उनके शो पर 80 और 90 के दशक के दो दिग्गज कलाकार पहुंचे हैं. एक है 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित और दूसरे हैं जग्गू दादा यानी जैकी श्राफ.

जैकी श्राफ और माधुरी दीक्षित दोनों ने ही बॉलीवुड में खास और बड़ा नाम कमाया है. दोनों का बॉलीवुड करियर लगभग साथ में ही शुरू हुआ था और इन दिग्गजों ने साथ में भी कई फिल्मों में काम किया है. हालांकि माधुरी जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस, दमदार डांसर और खूबसूरत अदाकारा के सामने जैकी श्राफ को रोमांटिक सीन करने में मुश्किल होती थी. माधुरी के सामने जैकी शर्मा जाते थे. ये खुलासा उन्होंने कपिल के शो पर माधुरी के सामने ही किया है. वहीं माधुरी ने बताया कि जैकी से पहली मुलाकात के दौरान वो काफी नर्वस हो गई थीं.

‘मुझे तिरछी नजर से देख रहे थे...’

कपिल शर्मा के शो पर माधुरी ने जैकी श्राफ से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया. उन्होंने साल 1986 में आई फिल्म 'कर्मा' सेट का एक किस्सा सुनाया. इस फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्राफ के अलावा कई कलाकार नजर आए थे. जबकि माधुरी दीक्षित ने इसमें एक गाना किया था.

दोनों एक्टर्स को लेकर माधुरी ने कहा, मैंने पहली बार कर्मा के सेट पर उन्हें देखा था. मैं फिल्म में एक छोटा सा गाना कर रही थी वहां अनिल जी और जग्गू दादा थे और दोनों ही तिरछी नजर से मुझे देखे जा रहे थे. उस वक्त मैं नई-नई थी और बहुत ज्यादा घबराई हुई थी. मेरा फिल्म में गाने के जरिए बहुत छोटा सा रोल था.

माधुरी-जैकी की फिल्में

माधुरी ने साल 1984 की फिल्म 'अबोध' से डेब्यू किया था. जबकि जैकी ने 1982 की फिल्म 'स्वामी दादा' में एक छोटे से रोल से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था. माधुरी और जैकी ने साथ में राम लखन, खलनायक, 100 डेज और परिदा जैसी फिल्मों में काम किया है.

‘प्यार के लिए कॉन्टिनेंट पार कर गई थी मैं...’, मृणाल ठाकुर ने खोले अपनी लव लाइफ के राज



फिल्मी है मृणाल का अंदाज

मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'दो दीवाने शहर में' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में वो सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ नजर आ रही हैं. हिंसा और एक्शन वाली फिल्मों के बीच एक सॉफ्ट रोमांटिक फिल्म लेकर थिएटर में एंट्री करने वाली इस जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान टीवी9 हिंदी डिजिटल के साथ की खास बातचीत में मृणाल ठाकुर ने बताया कि असल जिंदगी में वो कितनी फिल्मी हैं और उनके लिए प्यार के मायने क्या हैं. मृणाल 'दो दीवाने शहर में' आज कल की ट्रेंडी फिल्मों से बिल्कुल अलग है. तो इस फिल्म के लिए हां कहने की वजह क्या थी?

मृणाल का जवाब: सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने 'दो दीवाने शहर में' के लिए हां कहा. आज के समय में जब चारों तरफ हाई-एनर्जी ड्रामा और वायलेंस वाली फिल्मों में आ रही हैं, हम प्यार की एक ताजी हवा का झोंका लेकर आए हैं. आज लोग जब थिएटर से बाहर निकलते हैं, तब उनके बीच एक खूबसूरत बातचीत शुरू होती है और यही हमारा मकसद था और वो कामयाब हो रहा है. लोग मुझे 'थैंक यू' कह रहे हैं कि हमने कुछ फ्रेश बनाया है.

फिल्म का नाम 'दो दीवाने शहर में' है, क्या आप असल जिंदगी में कभी प्यार के लिए दीवाने हुई हैं, कुछ फिल्मी चीज की है?

मृणाल का जवाब: (हंसते हुए) बिल्कुल! मैं बहुत फिल्मी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरा 'लव लैंग्वेज' कालिटी टाइम बिताना है. एक बार मैं सिर्फ उस शख्स से मिलने के लिए 48 घंटों के लिए एक महाद्वीप (कॉन्टिनेंट) से दूसरे महाद्वीप तक का सफर तय कर गई थी. मेरे लिए उस इंसान के साथ वक्त बिताना, उसे सम्मान देना ही सबसे बड़ा फिल्मी जेस्चर है. लेकिन मुझे नहीं लगता ये फिल्मी है. अगर आपको सिद्धांत के किरदार 'शशांक' को मुंबई में डेट पर ले जाना हो, तो कहाँ ले जाएंगी?

मृणाल का जवाब: मैं सिद्धांत के किरदार को मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के सामने वाले एक रेस्टोरेंट 'सोम' में ले जाऊंगी. वहां का शाकाहारी खाना लाजवाब है. मैं उसे गन्ने का जूस, साबुदाना चढ़ा और थालीपीठ खिलाऊंगी. और हाँ, उसके बाद हम मंदिर में ही शादी कर लेंगे!

मृणाल अब एआई का जमाना है और इसकी मदद से सोशल मीडिया पर एक्टर्स को अक्सर निशाना बनाया जाता है, आपको लेकर भी हाल ही में कुछ अफवाहें उड़ी थीं. आप इन सब का किस तरह से सामना करती हैं?

मृणाल का जवाब: देखिए, लोग तो कहेंगे ही, उनका काम है कहना. एआई और फेक न्यूज के दौर में चीजें और मुश्किल हो गई हैं, लेकिन मैं बस मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हूँ. मैं इन चीजों से खुद को डिस्कनेक्ट रखती हूँ. मेरे बारे में जो अच्छी बातें लिखी गई हैं, उन्हें पढ़ती हूँ, क्योंकि निगेटिव चीजों पर मैं अपनी एनर्जी जाया नहीं करना चाहती.



भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बीच भारतीय सेना ने साफ संदेश दिया है कि अब पाकिस्तान की परमाणु धमकियों का कोई असर नहीं होगा। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लॉटिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा...

जन एक्सप्रेस



सम्पादकीय

'वोक' संस्कृति, वैचारिक सबवर्षण और भारतीय समाज पर गहरा खतरा

भारतीय चिंतन में कामना और संबंधों को सदैव जिम्मेदारी, संयम और सामाजिक संतुलन के साथ जोड़ा गया है। यहां स्वतंत्रता का अर्थ उच्छ्वेलता नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और कर्तव्यबोध से जुड़ा है। जब कला और अभिव्यक्ति के नाम पर किशोर जिज्ञासाओं को उन्मुक्त प्रयोग का क्षेत्र बना दिया जाता है, तब वह परंपरागत नैतिकता पर प्रश्नचिह्न लगाने के साथ-साथ भावनात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। परिवार और संस्कार को दमनकारी संरचना के रूप में प्रस्तुत करना व्यक्ति को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से दूर ले जा सकता है।

वर्तमान समय में भारतीय समाज एक ऐसे वैचारिक दौर से गुजर रहा है, जिसमें संस्कृति, परिवार, नैतिकता और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े प्रश्न नए रूप में सामने आ रहे हैं। भोपाल फिल्म फेस्टिवल को लेकर उठा विवाद किसी आयोजन की सामान्य नीति समीक्षा का विषय न होकर यह भारतीय समाज की वैचारिक दिशा और सांस्कृतिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। जिस आयोजन का सह-प्रस्तुतिकरण मध्यप्रदेश पब्लिक जैसी सरकारी संस्थान ने किया, वही मंच उन फिल्मों और व्यक्तियों को प्रदान करता दिखाई दिया, जो लंबे समय से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के विरोध में विचार अभिव्यक्ति चलाते रहे हैं। यह परिस्थिति संकेत देती है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में एक सुनियोजित वैचारिक प्रवाह सक्रिय है, जिसका लक्ष्य समाज की पारंपरिक संरचनाओं को बदलना है। पिछले वर्षों में 'वोक' और 'प्रगतिशील' जैसे आकर्षक शब्दों की आड़ में ऐसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ी है, जिनका उद्देश्य धीरे-धीरे सामाजिक मान्यताओं को परिवर्तित करना और नई मानसिकता को सामान्य बनाना है। इन आयोजनों में प्रस्तुत फिल्मों की विषयवस्तु पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि कथा और कला के माध्यम से वैचारिक संदेश स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप 'किस' (2022) और 'कुचुर (द इच)' जैसी फिल्मों की मूल थीम सामूहिकता, किशोर मनोविज्ञान और आनंद की अवधारणा को एक विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती हैं। इन फिल्मों के माध्यम से ऐसे विषयों को केंद्र में रखा गया है, जो भारतीय पारिवारिक और सामाजिक संरचना में संवेदनशील माने जाते हैं। निर्देशक चरण ग़ोवर जैसे व्यक्तित्व, जो लंबे समय से वामपंथी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं और सरकार, भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर खुली टिप्पणियों के लिए चर्चित रहे हैं, ऐसे आयोजनों में प्रमुख स्थान प्राप्त करते हैं। तब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या करदाताओं के धन का उपयोग उन कार्यक्रमों के लिए किया जाना उचित है, जो भारतीय समाज की परंपरागत मान्यताओं और राष्ट्रवादी विमर्श की आलोचना को प्रोत्साहित करते हैं। यह प्रश्न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरोध का नहीं, बल्कि राज्य की वैचारिक तटस्थता और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का है। वोक विचारधारा को यदि गहराई से समझा जाए तो यह महज सामाजिक जागरूकता का आंदोलन नहीं प्रतीत होती, सांस्कृतिक मार्क्सवाद की आधुनिक अभिव्यक्ति के रूप में उभरती है। इसका लक्ष्य समाज की पारंपरिक इकाइयों जैसे परिवार, धर्म, संस्कृति, स्त्री-पुरुष संबंध और नैतिक अनुशासन को पुनर्निर्धारित करना है। इस विचारधारा में व्यक्ति को सामूहिकता से ऊपर रखा जाता है, इच्छा को मर्यादा से अधिक महत्व दिया जाता है और आनंद को जीवन का मूल मूल्य घोषित किया जाता है। फिल्मों और दृश्य माध्यम इस दिशा में अत्यंत प्रभावी साधन बन जाते हैं, क्योंकि वे भावनाओं, कथानक और कला के आवरण में विचारों को सहज रूप से स्थापित कर देते हैं। किशोरवस्था जीवन का अत्यंत संवेदनशील चरण है। इस आयु में प्रस्तुत कथाएँ और दृश्य लंबे समय तक मानसिक संरचना को प्रभावित करते हैं, तो कुछ लोग फायदेमंद हैं? कुछ लोग सुबह की ताजी हवा में टहलना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग रात के खाने के बाद हल्की वॉक को बेहतर मानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डिन्नर के बाद वॉक करना मॉर्निंग वॉक से ज्यादा फायदेमंद है? क्या डिन्नर के बाद टहलना मॉर्निंग वॉक से बेहतर है? डॉक्टर जी कृष्ण मोहन रेड्डी का कहना है कि दोनों के अपने-अपने फायदे हैं, लेकिन व्यक्ति की दिनचर्या और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सही समय चुनना चाहिए। सुबह की वॉक जहाँ मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है और मानसिक ताजगी देती है, वहीं डिन्नर के बाद की वॉक पाचन सुधारने और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद कर सकती है। मॉर्निंग वॉक: वॉकिंग वॉक से शरीर को



ललित गर्ग

यह कार्य करने की मानसिकता को बाधित करती है और समाज में सरकार-निर्भरता एवं अकर्मण्यता की संस्कृति को जन्म देती है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो आर्थिक असंतुलन और राजनीतिक अविश्वास दोनों बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि नीतियों की पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और चुनावी निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

भारतीय लोकतंत्र की विडंबना यह है कि चुनाव आते ही जनसेवा का स्वरूप बदलकर जनलुभावन राजनीति में परिवर्तित हो जाता है। राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनावी सफलता का शॉर्टकट बना लिया है। मतदाताओं को तात्कालिक आर्थिक लाभ देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लगातार मजबूत हो रही है। आगामी तीन-चार माह में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी संदर्भ में जब अरम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक सरामियां तेज हुईं, तब इस संस्कृति का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी पृष्ठभूमि में देश की शीर्ष अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, ने मुफ्त की योजनाओं के अनियंत्रित विस्तार पर गंभीर टिप्पणी की। यह टिप्पणी केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को लेकर एक चेतावनी है। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरिक्त उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं। जब राजस्व घाटे से जुड़े रहे राज्य मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा या नकद वितरण की घोषणाएं करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि यह संसाधन कहाँ से आएंगे और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? राजकोषीय अनुशासन किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का आधार है। यदि राज्य अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए रज्ज्वाने को खुला कर देता है, तो दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। जो धन बुनियादी ढांचे के निर्माण, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार और रोजगार सृजन में लगाना चाहिए, वह वोटों की फसल काटने में खर्च हो जाता है। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। लोकतंत्र में मतदाता की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी जाती है। यदि मतदाता को परोक्ष रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर प्रभावित किया जाता है, तो यह स्वतंत्र निर्णय की भावना को कमजोर करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने तार्किक प्रश्न उठाया कि राज्य रोजगार सृजन और कौशल विकास पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते? वास्तव में रोजगार ही स्थायी संपत्तीकरण का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने श्रम और कौशल से आय अर्जित करता है, तब उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। इसके विपरीत, निरंतर मुफ्त सुविधाएँ व्यक्ति को निर्भर बनाती हैं। धीरे-धीरे परिश्रम की संस्कृति कमजोर

एक्सप्रेस आलेख

विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पिछले साल अक्टूबर में आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 15,600 करोड़ रुपये दिए गए थे। जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कदम था। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपरोक्ष रूप से रिश्वत देने के प्रयासों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही इस दिशा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई भी करनी चाहिए। निर्विवाद रूप से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिये हानिकारक है।

मुफ्त रेवड़ी संस्कृति जीवंत लोकतंत्र के लिये घातक



लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं।

कोशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें। यह भी समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं का हर स्वरूप गलत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत देना, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पहुंचाना, सामाजिक न्याय के तहत वंचित वर्गों को अवसर देना-ये सब राज्य की जिम्मेदारी हैं। परंतु चुनावी मौसम में अचानक घोषणाओं की बाढ़ आ जाना और दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों की अनदेखी करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत नहीं है। यह राजनीतिक दलों के वैचारिक दिवालियेपन को दर्शाता है, जहां दूरदृष्टि की जगह तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल संस्थाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सजगता से भी आती है। यदि मतदाता केवल तात्कालिक लाभ देखकर मतदान करता है, तो वह अनजाने में ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जो अंततः उसी के भविष्य को प्रभावित करती है। परिपक्व मतदाता वही है जो घोषणाओं के पीछे की मंशा और आर्थिक व्यवहार्यता को समझे। वह यह पूछे कि पांच साल बाद राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विकास की दिशा क्या होगी और रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे। लोकतंत्र में वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज भारत स्वयं को वैश्विक मंच पर एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। हम विश्वगुरु बनने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यदि हमारी राजनीति लोकलुभावनवाद के जाल में उलझी रहेगी, तो यह संकल्प खोखला सिद्ध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव तभी सार्थक है जब हमारी नीतियां दूरदर्शी, संतुलित और टिकाऊ हों। मुफ्त की संस्कृति से बाहर निकलकर उत्पादकता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। यह समय आत्ममंथन का है। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि जनता को सशक्त बनाना केवल धन बांटने से संभव नहीं है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार-ये चार स्तंभ किसी भी राष्ट्र की मजबूती तय करते हैं।



आज का पंचांग

किरीं औं शुभ कार्य को करने के लिए सही सुहूर्त, सही समय, और सही नवग्रह का होना जरूरी होता है, आज हम आपको आज के दिन का सही समय जो की सही कार्य करने का है, और आज कब कौन सी दशा फलन से टाड़ना नौ पल रहे है उसका समुचित विवरण हिन्दू कैलेंडर और हिन्दू पंचांग के अनुसार दे रहे है, आज आपका दिन मंगलवारी रहे, यही शुभकामना है। आज का दिन शुभ कार्य के लिए सही कार्य है या नहीं आज के पौर्णिमा के अनुसार जानो। अगर आप आज वास्तु खरीदने का विचार कर रहे है या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे है, गृह प्रवेश कर रहे है, गृह निर्माण कर रहे है, प्रार्थना कर रहे है, या कोई अन्य शुभ कार्य करने के लिए सोच रहे है तो पहले यहाँ सही समय देख लें, आकाश कार्य शुभ और सफल होगा, सही वस्ती और से शुभ मंगल कामना है।

तिथि:	एकदशी 10:33 तक
नक्षत्र:	आशु 10:48 तक
पक्ष:	शुक्ल
वार:	शुक्रवार
राशि:	आशुमान, 07:43
सूर्यास्त:	06:54
सूर्योदय:	18:25
चंद्रमा:	मिथुन राशि में
राहुकाल:	11:13-12:39
किरीं नी संवत्:	2082
शक संवत्:	1947
मास:	फाल्गुन
शुभ सुहूर्त:	12:16-13:02

जन एक्सप्रेस

फिसल रही जुबान !

बहसबाजी घरम ।
फिसल रही जुबान ॥
है आतुर अब सारे ॥
पाने को सम्मान ॥
नीचा उन्हें दिखाना ॥
है हमको हर हाल ॥
है चुनावी बेला ॥
उठने दो सवाल ॥
माहिर होने खातिर ॥
जायी है प्रयास ॥
होके रहेंगे अब तो ॥
हम ही सबके तयास ॥
है खाका है ध्यान ॥
उसी तरफ है ध्यान ॥
बोलकर अपशब्द ॥
छूना असमान ॥



कृष्ण सिंह राय

एक्सप्रेस स्वास्थ्य

क्या डिन्नर के बाद टहलना मॉर्निंग वॉक से बेहतर है?

आज की बिजी लाइफस्टाइल में लोगों के पास जिम जाने का समय नहीं होता, इसलिए वॉक सबसे आसान और असह्यद एक्सरसाइज मानी जाती है, लेकिन सही समय का चुनाव कई बार उलझन पैदा कर देता है। क्या सुबह खाली पेट चलना फिट बर्निंग को तेज करता है? क्या रात में खाने के बाद टहलने से वजन बढ़ने से रोका जा सकता है? क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए डिन्नर के बाद वॉक ज्यादा फायदेमंद है? कुछ लोग सुबह की ताजी हवा में टहलना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग रात के खाने के बाद हल्की वॉक को बेहतर मानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डिन्नर के बाद वॉक करना मॉर्निंग वॉक से ज्यादा फायदेमंद है? क्या डिन्नर के बाद टहलना मॉर्निंग वॉक से बेहतर है? डॉक्टर जी कृष्ण मोहन रेड्डी का कहना है कि दोनों के अपने-अपने फायदे हैं, लेकिन व्यक्ति की दिनचर्या और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सही समय चुनना चाहिए। सुबह की वॉक जहाँ मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है और मानसिक ताजगी देती है, वहीं डिन्नर के बाद की वॉक पाचन सुधारने और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद कर सकती है। मॉर्निंग वॉक: वॉकिंग वॉक से शरीर को



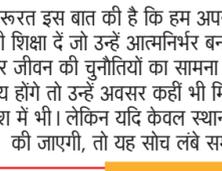
ताजी ऑक्सीजन मिलती है, जिससे फेफड़े बेहतर काम करते हैं और मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है। सुबह खाली पेट हल्की वॉक करने से फिट बर्निंग प्रोसेस तेज हो सकती है। डॉक्टर जी कृष्ण मोहन रेड्डी के अनुसार, सुबह की वॉक मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह तनाव कम करती है, सुक बेहतर बनाती है। और डिन्नर के लिए पॉजिटिव एनर्जी देती है। नियमित मॉर्निंग वॉक ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में भी मददगार हो सकती है। डिन्नर के बाद वॉक: डॉक्टर जी कृष्ण मोहन रेड्डी बताते हैं कि डिन्नर के तुरंत बाद बैठ जाने या लेट जाने से गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में हल्की वॉक ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने और भोजन के पाचन में मदद कर सकती है। खासकर

डायबिटीज के मरीजों के लिए डिन्नर के बाद वॉक फायदेमंद मानी जाती है क्योंकि यह भोजन के बाद ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। हालांकि, बहुत तेज या लंबी वॉक करने से बचना चाहिए। डिन्नर के बाद हल्की वॉक करने से शरीर रिलैक्स होता है और नींद की क्वालिटी बेहतर हो सकती है लेकिन बहुत देर रात या ज्यादा तेज वॉक करने से कुछ लोगों में नींद प्रभावित हो सकती है। स्टडी क्या कहती है?: स्टडी के अनुसार, रात के खाने या लंच के तुरंत बाद टहलना वजन घटाने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए सुबह की सैर या भोजन के लंबे समय बाद टहलने से अधिक प्रभावी है। भोजन के तुरंत बाद 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करने से शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम रहता है, जिससे इंसुलिन का रिलीज कम होता है। यदि आपको पेट में दर्द या कोई असुविधा नहीं होती है, तो खाने के तुरंत बाद टहलना स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। निष्कर्ष: यह कहना गलत नहीं होगा कि मॉर्निंग वॉक और डिन्नर के बाद वॉक, दोनों के अपने फायदे हैं। बेहतर क्या है, यह आपकी दिनचर्या, स्वास्थ्य स्थिति और टारगेट पर निर्भर करता है।

एक्सप्रेस विशेष

विदेश भेजने की होड़ और बदलती मानसिकता

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में नई प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है, बेटे-बेटियों को विदेश भेजने की होड़। कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, तो कभी बेहतर जीवन के सपने के साथ। कई परिवारों में यह उल्लब्धि की तरह प्रस्तुत किया जाता है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। किसी का कनाडा जाना, किसी का ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जाना-यह सब मानो सफलता की पहचान बन गया है। धीरे-धीरे यह धारणा बनती जा रही है कि यदि भविष्य बनाना है तो विदेश जाना पड़ेगा। लेकिन यह सवाल गंभीरता से पूछने की जरूरत है कि क्या वास्तव में भारत में अवसरों की कमी है? क्या इस देश में प्रतिभा को लिए जगह नहीं बची? या फिर हम स्वयं अपने देश की संभावनाओं को कम आंकने लगे हैं? भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। तकनीक, उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में लगातार नए अवसर पैदा हो रहे हैं। दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भारत में निवेश कर रही हैं। लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। छोटे शहरों और कस्बों से निकल कर



डॉ. प्रियंका सौरभ

जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सक्षम बनाएं। उन्हें ऐसी शिक्षा दे दें जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, उनमें कौशल विकसित करे और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दे। अगर युवा योग्य होंगे तो उन्हें अवसर कहीं भी मिल सकते हैं- भारत में भी और विदेश में भी। लेकिन यदि केवल स्थान बदलने से सफलता की उम्मीद की जाएगी, तो यह सोच लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी।

युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। ऐसे में यह मान लेना कि भविष्य केवल विदेश में ही है, एक अधुरी और जल्दबाजी वाली सोच लगती है। विदेश जाने की एक बड़ी वजह शिक्षा भी है। कई छात्र यह सोचकर विदेश जाते हैं कि वहाँ की पढ़ाई बेहतर है या वहाँ अवसर अधिक हैं। कुछ मामलों में यह सही भी हो सकता है। लेकिन एक सच्चाई यह है कि कई छात्र केवल इसलिए विदेश चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत में मनचाहे कॉलेज या कोर्स में प्रवेश नहीं मिल पाता। प्रतियोगिता कटिन्त है, सीटें सीमित हैं और हर किसी को प्रतिष्ठित संस्थानों में जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में विदेश जाना विकल्प बन जाता है। लेकिन इस प्रक्रिये को सामाजिक प्रतिष्ठता का प्रतीक बना देना चिंताजनक है। आज स्थिति यह हो गई है कि कई जगहों पर माता-पिता अपने बच्चों को

अकेलेपन का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनकी कल्पना भारत में रहते हुए नहीं की जाती। लेकिन यह सच्चाई अवसर तस्वीरों और वीडियो के पीछे छिप जाती है। समस्या विदेश जाने में नहीं है। समस्या उस मानसिकता में है जिसमें विदेश को सफलता का पर्याय बना दिया गया है। दुनिया को देखने, नई शिक्षा और अनुभव प्राप्त करने के लिए विदेश जाना अच्छा अवसर हो सकता है। कई भारतीय छात्र विदेश में उच्च शिक्षा लेकर नई तकनीक और ज्ञान प्राप्त करते हैं और बाद में देश के विकास में योगदान भी देते हैं। लेकिन जब यह निर्णय समझदारी के बजाय भीड़ का हिस्सा बनकर लिया जाता है, तब कई बार परिणाम निराशाजनक भी हो सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग है। आज का युवा पहले से अधिक जागरूक, शिक्षित और तकनीक से जुड़ा हुआ है। स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। छोटे शहरों के युवा भी अब सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। डिजिटल युग में अवसरों की सीमाएँ पहले जैसी नहीं हैं।

तहसील काँच और नगर पालिका उरई का डीएम ने किया निरीक्षण

लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण, राजस्व वसूली में तेजी और जनसुविधाओं में सुधार के सख्त निर्देश

जन एक्सप्रेस | उरई

जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने तहसील काँच तथा नगर पालिका परिषद उरई का निरीक्षण कर विभिन्न पटलों की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। तहसील काँच पहुंचकर जिलाधिकारी ने विभिन्न पटलों का मुआयना करते हुए पत्रावलियों के रख-रखाव, रिकॉर्ड संभारण व्यवस्था एवं अभिलेखों की स्थिति का बारीकी से परीक्षण किया। सर्विस बुक एवं जीपीएफ पासबुक के अवलोकन के दौरान पाई गई विषमताओं के निराकरण हेतु नायब तहसीलदार को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस एवं जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता पूर्ण एवं समयबद्ध

निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिकायत पत्रिका में दर्ज चार शिकायतकर्ताओं से स्वयं दूरभाष पर वार्ता कर निस्तारण की वास्तविक स्थिति जानी, जिसमें सभी संतुष्ट पाए गए। तहसील न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए तीन वर्ष एवं पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही आरसीपीएमएस पोर्टल पर लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण एवं रियल टाइम खतौनी पोर्टल पर अभिलेख अद्यतन रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष रूप से 10 बड़े बकायेदारों की सूची तालब करते हुए उनकी संपत्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता



बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खतौनी कक्ष, लिपिक कार्यालय, पूर्ति निरीक्षक कार्यालय एवं संग्रह अमीन कार्यालय का निरीक्षण कर रिकॉर्ड सुव्यवस्थित रखने एवं लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद उरई का निरीक्षण कर नगर क्षेत्र की

व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा सभी वार्डों के सभासदों के साथ संवाद किया। सभासदों द्वारा खराब सड़कों, स्ट्रीट लाइट एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं रखी गईं। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जगह-जगह के कार्यों में लापरवाही न बरती जाए और प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। अंधेरे वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर शीघ्र स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त

डंपर की टक्कर से महिला की मौत, परिजनों में कोहराम

जन एक्सप्रेस | उरई

चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम औता के पास तालाब के समीप डंपर की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को तत्काल मेडिकल कॉलेज भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार इवेंट नंबर 6567 पर पीआरवी 8352 को सूचना मिली कि ग्राम औता के तालाब के पास एक बाइक में डंपर ने टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक पर सवार मुन्नी

देवी 55 पत्नी विद्या शंकर कुशवाहा निवासी ग्राम बाबई, थाना चुर्खी घायल हो गई थी। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज उरई भेजा गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में थाना अध्यक्ष ने बताया कि हादसे में शामिल डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

डीसीएम व कार की आमने-सामने भिड़ंत, तीन घायल, गंभीर

उरई। काँच कोतावाली क्षेत्र में बुधवार की देर रात एक कार काँच की ओर जा रही थी और काँच की ओर से एक डीसीएम मटर लाइकर जालौन की ओर आ रही थी। काँच रोड पर देवरी और उदोतपुरा के बीच दोनों वाहन आमने सामने आ गए और उनके बीच जोरदार टक्कर हो गई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कोतावाली क्षेत्र के ग्राम सिकरी राजा निवासी कार सवार सुमित, सोनील व दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से निकल रहे लोगों ने हादसे की सूचना युपी 112 को दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उच्च संस्थान रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर कोतावाली में खड़ा कराया है।

भाई की जमीन पर कब्जा किया, रिपोर्ट दर्ज

जन एक्सप्रेस/शाहाबाद। एक

भाई ने दूसरे भाई की जमीन पर कब्जा कर लिया और उस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास की कॉलोनी बनानी प्रारंभ कर दी। भाई ने जब मना किया तो भाई और भौजाई को पीट कर घायल कर दिया। घटना की नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शाहाबाद कोतावाली के मौलागंज निवासी याकूब पुत्र रसाहक के अनुसार उसके भाइयों में बंटवारा हो गया। छोटे भाई आफाक की प्रधानमंत्री कॉलोनी मंजूर हो गई और उसने उसकी जमीन पर बनाना प्रारंभ कर दिया। जब मना किया तो ने आफाक ने याकूब और उसकी पत्नी अमीना को पीटकर घायल कर दिया। घटना की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घायल पति-पत्नी का डाक्टरों परीक्षण कराया गया।

अराजकतत्वों ने मंदिर से मूर्तियां उखाड़कर किया माहौल बिगाड़ने का प्रयास

जन एक्सप्रेस | माधौगढ़

कस्बा के उत्तरीय मालवीय नगर के रामहेतपुरा रोड के पास गणेश जी मंदिर स्थापित है। उसी के थोड़ी दूरी पर शिव मंदिर बना हुआ है। उसमें तीन छोटी छोटी मूर्तियां शिव, पार्वती व कार्तिकेय की स्थापित थी। बताया गया है कि देर रात शिव मंदिर में स्थापित शिव, पार्वती व कार्तिकेय की मूर्तियां उखाड़ कर ले गए। अधिवक्ता महेश शर्मा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी है। कोतवाल विवेक बाबू का कहना है कि अधिवक्ता महेश शर्मा से बातचीत हो गई, शीघ्र ही मूर्तियां की स्थापना करा दी जाएगी।

अज्ञात कारणों के चलते ट्रेन से कटकर शिक्षक की मौत

जन एक्सप्रेस | उरई

एट थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर शिक्षक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। हरनाम सिंह अर्ध मत्त पुत्र गोविंद सिंह निवासी नुनवाई थाना कोटरा हाल मुकाम एट में अपनी निज निवास पर रहते थे। बताया गया कि वह वृद्धस्यतिवार सुबह बाइक पर सवार होकर घर से निकला था। जिसने पिंडारी क्रांति से 1 किलोमीटर आगे की ओर रेलवे ट्रैक के पास बाइक खड़ी करके ट्रेन से कटकर जान दे दी। इस दौरान वहां पास के खेतों पर काम कर रहे किसानों ने जब हादसे को देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची

पुलिस ने लोगों से जानकारी जुटाने पर हरनाम के रूप में शिनाख्त कर खबर उसके परिजनों को दी। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और वह तेरे बिलखते मौके पर पहुंच गए। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया की मृतक झांसी जिले के पट्टा गांव में जूनियर स्कूल में बाबू के पद पर तैनात था। जिसका रोज एट से पट्टा बाइक द्वारा आना-जाना रहता था। बताया कि मृतक के दो बेटियां एक लड़का है, जिसमें एक बेटी की शादी हो चुकी है। वहीं पत्नी मंजू का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच को देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची

भूमि संरक्षण राष्ट्रीय जलागम द्वितीय का कार्यालय से गायब रहना बना चर्चा

जन एक्सप्रेस | उरई

प्रदेश के मुखिया का नजदीकी बताकर हर किसी पर रौब गालिब करने वाले भूमि संरक्षण अधिकारी राष्ट्रीय जलागम, जालौन द्वितीय जिसका कार्यालय संबंधित विकासखंड में नहीं बल्कि जिला मुख्यालय के बोहदपुरा स्थित कृषि फार्म में जहां अक्सर ही अपनी इयूटी से भूमि संरक्षण अधिकारी गायब रहकर मौज काट रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में भूमि संरक्षण अधिकारी प्रदेश के मुखिया के नजदीकी भी हैं या फिर वह गम्पबाजी कर रूआब गांठते हैं, यह जांच का विषय हो सकता है। यह पता चल रहा है कि भूमि संरक्षण अधिकारी राष्ट्रीय जलागम, जालौन द्वितीय का कार्यक्षेत्र



कुर्चैद व रामपुरा विकासखंड है तो ऑफिस भी जालौन तहसील या माधौगढ़ तहसील में होना चाहिए। लेकिन उसका मुख्य कार्यालय जिला मुख्यालय से दूर जालौन रोड स्थित बोहदपुरा कृषि फार्म परिसर में बना हुआ है। जहां भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में कभी भी नियमित नहीं आते हैं। जब भी

उनके कार्यालय में संपर्क किया जाता है तो बताया जाता है कि साहब प्रदेश के मुखिया के नजदीकी बताते हैं जिसकी वजह से हम लोग भी अपनी नौकरी सुरक्षित कर अपना मुंह बंद रखने में भलाई समझते हैं। हैदराबाद कोतावाली के मौलागंज निवासी याकूब पुत्र रसाहक के अनुसार उसके भाइयों में बंटवारा हो गया। छोटे भाई आफाक की प्रधानमंत्री कॉलोनी मंजूर हो गई और उसने उसकी जमीन पर बनाना प्रारंभ कर दिया। जब मना किया तो ने आफाक ने याकूब और उसकी पत्नी अमीना को पीटकर घायल कर दिया। घटना की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घायल पति-पत्नी का डाक्टरों परीक्षण कराया गया।

सीएसएन कालेज में हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक

जन एक्सप्रेस | हरदोई

हरदोई में सीएसएन पीजी कॉलेज के हीरक जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। और मंच पर आते ही उन्होंने औपचारिक भाषण के बजाय हरदोई की स्थानीय बोली में संवाद शुरू किया, जिससे छात्र-छात्राओं में उत्साह का माहौल बन गया। उन्होंने अपने छात्र जीवन से जुड़ी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि समय के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन हरदोई की पहचान और आत्मीयता आज भी कायम है। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कॉलेज के संस्थापक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहनलाल वर्मा को नमन करते हुए कहा कि उनका परिवार वर्षों से वर्मा परिवार के संपर्क में रहा है और वे बचपन में अपने पिता के साथ इस परिवार में आया करते थे। उन्होंने पुराने समय की परिवहन और बिजली व्यवस्था की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमित



संसाधनों के बावजूद शिक्षा के प्रति लगन कम नहीं थी। छात्रों से संवाद करते हुए उन्होंने दलेलनगर, बावन, बालामऊ और कछौना जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों का विशेष उल्लेख किया और मन लगाकर पढ़ाई करने, शिक्षकों से संवाद बनाए रखने तथा सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने संत कवि सूरदास, कबीर और रहीम के दोहों का उल्लेख किया तथा

चंद्रशेखर आजाद को स्मरण करते हुए युवाओं से महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। समारोह के अंत में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एमएलसी सतीश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अंबिका त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती वर्मा और प्राचार्य कौशलेंद्र सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

हरदोई में परीक्षा से घर लौट रही छात्रा पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस | हरदोई

हरदोई जनपद के लोनार थाना क्षेत्र में जगदीशपुर गांव स्थित एक इंटर की परीक्षा देकर घर लौट रही एक छात्रा पर मनचले युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार छात्रा ने तीन दिन पूर्व छेड़खानी की शिकायत लोनार कोतावाली में दी थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि पंकज पुत्र रामरूप निवासी अस्लापुर ने पीछे से बांके से वार किया। परिजनों का कहना है कि आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहा था और मना करने पर उसने वादतात को अंजाम दिया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। छात्रा का आरोप है कि उसने पूर्व में पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पश्चिमी मार्टिड प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

तीन दिन पूर्व छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने नही की कार्रवाई, दो पुलिसकर्मी निलंबित



एसपी मार्टिड प्रकाश सिंह ने बताया कि छात्रा द्वारा पूर्व में की गयी शिकायत को ध्यान में रखते हुए तीन दिन पूर्व छेड़खानी की शिकायत लोनार कोतावाली में दी थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि पंकज पुत्र रामरूप निवासी अस्लापुर ने पीछे से बांके से वार किया। परिजनों का कहना है कि आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहा था और मना करने पर उसने वादतात को अंजाम दिया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। छात्रा का आरोप है कि उसने पूर्व में पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पश्चिमी मार्टिड प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

गॉलब्लेडर के खिलाफ समय पर जांच ही सबसे बड़ा बचाव

लखनऊ। गॉलब्लेडर (पिताशय) कैसर भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है, विशेष रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, जिसमें उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्य शामिल हैं। इस बीमारी के स्पष्ट शुरुआती लक्षण नहीं होते और इसके संकेत अक्सर सामान्य गॉलब्लेडर संबंधी समस्याओं समझ लिए जाते हैं, जिस कारण अधिकांश मामलों में इसका पता देर से और एडवांस स्टेज में चलता है। फरवरी की गॉलब्लेडर कैसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, ऐसे में इसके चेतावनी संकेतों और उपलब्ध उपचार विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है ताकि इस बीमारी का बोझ कम किया जा सके। नानावती मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एपीबी एवं जीआई सर्जरी विभाग के वाइस चेयरमैन और शोध एवं स्टूडी, ऑनकोलॉजी विभाग के, लीड डॉ. गणेश नागराज ने बताया गॉलब्लेडर कैसर के सामान्य रेड फ्लैग संकेतों में पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द, आंखों या त्वचा का पीला पड़ना (पीलीया), लगातार मतली या उल्टियां, बिना कारण वजन कम होना, बुखार, कुछ मामलों में पेट में गांठ महसूस होना या पित्त नली में रुकावट के लक्षण शामिल हैं।

बूथ अध्यक्ष की पत्नी को उच्च शिक्षा मंत्री ने दी दो लाख की सहायता राशि

जन एक्सप्रेस | शाहाबाद

शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के मोहल्ला खलौल निवासी बूथ अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे उर्फ गौरी की मौत के बाद आर्थिक तंगी से गुजर रहे परिजनों को उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी द्वारा गुल्बर्गा को अपने आवास पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से निर्गत दो लाख की आर्थिक सहायता का चेक मृतक की पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी को प्रदान किया गया। इस सहयोग राशि से आर्थिक तंगी से गुजर रहे परिवार को राहत मिली है। लगभग पांच माह पूर्व मौत हो गई थी। उसके बाद से शैलेंद्र पांडे का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक और प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर



उनका आर्थिक सहयोग करने का आश्वासन दिया था। अपने इस आश्वासन के अंतर्गत उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन सहायता कोष से मृतक की पत्नी को दो लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इस मौके पर तहसील प्रशासन, भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल पांडे पिंटू, केन ग्रोवर्स अध्यक्ष रंजीत सिंह, मृतक के पिता रामलाल, भाई विपिन आदि मौजूद रहे।

हरदोई के सांडी में पटाखा बनाते समय दो मजिला घर में विस्फोट, दो महिलाएं घायल

जन एक्सप्रेस | हरदोई

जनपद के सांडी कस्बे में होली के त्योहार पर एक दो मजिला घर के अंदर पटाखा बनाते समय जबरदस्त विस्फोट हो गया। इस हादसे में मकान का भवन गिरने के साथ-साथ दो महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटाखों के विस्फोट की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग भी सहम गए। और सैकड़ों की तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए। जानकारी के अनुसार सांडी कस्बे के मोहल्ला औलादगंज निवासी दिलशाद को कस्बे के बाहर पटाखा बनाने की दुकान है। गुरुवार की शाम दिलशाद की पत्नी साजिया (30) व



उसकी देवरानी रूबीना (25) पत्नी इरशाद दो मजिला मकान में होली त्योहार के मद्देनजर पटाखा बना रही थी। उसी समय पटाखों में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। बारूदी विस्फोट होने से दूर तक आवाज सुनाई पड़ी। धमाका इतना जोरदार था दो मजिला इमारत की दीवारों में दरारें आ गईं। इस विस्फोट में देवरानी व जेटनी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जाता है की 14 साल पहले 2012 में ही घर के अंदर बड़ा विस्फोट हो गया था जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

बच्चों को चिन्हित कर सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित करें: डीएम

जन एक्सप्रेस | हरदोई

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स एवं बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति की बैठक आहूत की गयी। जिलाधिकारी ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिये कि जनपद के ईट भट्टा, होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री आदि स्थलों पर जोखिमारी कर बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराएँ। उन्होंने कहा कि बच्चों को चिन्हित कर उनको सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं का लाभ दिया जाये। उन बच्चों को बाल सेवा योजना से जोड़ा जाये, बालिकाओं का कस्टर्वा विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाये। बच्चों के परिवार को चिन्हित कर राशन कार्ड, उच्चवला योजना का लाभ दिलाया जाये। उन्होंने कहा कि 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें



खतरनाक कार्यों के प्रति दूर रखने हेतु अभियान चलाकर उनके अभिभावकों को जागरूक करें बच्चों को शिक्षित बनाये और बाल श्रम न कराये। बैठक में समिति के सदस्यों ने बाल श्रम रोकने हेतु अपने विचार व्यक्त किये। बैठक में सहायक श्रमायुक्त सत्यवीर सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए अशोक कुमार मौर्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम, समिति के सदस्य शत्रुघ्न द्विवेदी, आदि उपस्थित रहे।

बी-सी ग्रेड योजनाओं पर प्रभारी मंत्री का कड़ा रुख, प्रगति सुधारने का अल्टीमेटम

जन एक्सप्रेस | महाराजगंज



जनपद के प्रभारी मंत्री/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. दयाशंकर मिश्रा दयालु ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने कार्यवाही संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी परियोजनाएं गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समयसीमा में पूर्ण की जाएं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए तथा परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित जनप्रतिनिधियों को समय-समय पर अवगत कराया जाए। उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने के निर्देश भी दिए।

डीएम एसपी ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण



जन एक्सप्रेस | महाराजगंज

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मोना ने बुधवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सामान्य बैक, महिला बैक, कारागार चिकित्सालय, पाकशाला तथा जेल परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया।

महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम

जन एक्सप्रेस | प्रतापगढ़

जिले के मंगरीवा विकासखंड के सभागार में गुरुवार को ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्लाक प्रमुख राजीव प्रताप सिंह, बीडीओ राजीव पाण्डेय, थाना प्रभारी धननयन राय, मिशन शक्ति टीम प्रभारी राजकुमार मिश्र व विनोद पाण्डेय मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं को स्वरोजगार, कानूनी अधिकारों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि वे आर्थिक व सामाजिक रूप से स्वावलंबी बन सकें। बीडीओ राजीव पाण्डेय ने ग्राम पंचायतों, पंचायती राज संस्थाओं और जीविका समूहों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं के



प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहभागिता आधारित मॉडल अपनाया जा रहा है। प्रशिक्षण में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में महिलाओं की भूमिका और सहभागिता को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान ब्लाक प्रमुख राजीव प्रताप सिंह ने कहा कि

स्वयं सहायता समूहों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच मजबूत तालमेल से गांवों में विकास की रफ्तार तेज होगी और इसका लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल महिला नेतृत्व और आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारी

प्रोत्साहन मिल सके। मंत्री ने अधिकारियों से विभागों में नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यटन, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश को वन टूरिज्म डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में जनपद की उल्लेखनीय भूमिका सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जिलाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी अधिकारियों को मंत्री के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। इससे पूर्व जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री व जनप्रतिनिधियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रविशंकर पटेल, विधायक पनियारा ज्ञानेंद्र सिंह, विधायक नौतनवा ऋषि त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, एडीएम (वि/रा) डॉ. प्रशांत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सांसद की अध्यक्षता में निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न

जन एक्सप्रेस प्रतापगढ़। जिले में गुरुवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक विकास भवन स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय सभागार में सम्पन्न हुई। जिसमें सांसद एसपी सिंह पटेल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधायक रानीगंज आरके वर्मा, विधायक जीतलाल पटेल, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्था, पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दिव्या मिश्रा तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधिगण के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान केन्द्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता से जुड़े योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा जन सुविधाओं से जुड़े अनेक सुझाव और समस्याओं को भी रखा गया। जिसके समाधान के निर्देश समिति द्वारा अधिकारियों को दी गई। योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए स्थानीय समस्याओं एवं सुझावों पर विचार-विमर्श कर उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष एसपी सिंह पटेल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़ी जो शिकायतें व फीडबैक रखा गया है। उसे अधिकारी गंभीरता से लेते हुए समय सीमा के अन्दर उसका समाधान कराएँ। विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए रोड मैप तैयार कर कार्य किए जाएँ। अधिकारी व जनप्रतिनिधि जिले के विकास के लिए आगे आकर टीम भाव से कार्य करें। जिससे कि विकास की दिशा में जिला अग्रणी रहे।

सांसद की अध्यक्षता में निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न

जन एक्सप्रेस/महोबा। विकासखंड पनवाड़ी की ग्राम पंचायत सलेया खालसा में गौशाला के जानवरों द्वारा किसानों की गन्ने की फसल बर्बाद किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि गौशाला में लगभग एक डेढ़ड़ से अधिक निराश्रित पशु संरक्षित हैं, जिनके लिए शासन स्तर से भूसा-चारा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा पशुओं को खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। किसानों के मुताबिक, इस समय उनके खेतों में गन्ने की फसल लहलहा रही थी, लेकिन गौशाला से छोड़े गए जानवरों ने करीब 9 से 10 बीघा फसल पूरी तरह चोपट कर दी। किसानों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पहले ग्राम प्रधान से शिकायत की, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

गौशाला के जानवरों ने उजाड़ी 10 बीघा गन्ने की फसल, किसानों ने थाने में दी तहरीर

जन एक्सप्रेस/महोबा। विकासखंड पनवाड़ी की ग्राम पंचायत सलेया खालसा में गौशाला के जानवरों द्वारा किसानों की गन्ने की फसल बर्बाद किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि गौशाला में लगभग एक डेढ़ड़ से अधिक निराश्रित पशु संरक्षित हैं, जिनके लिए शासन स्तर से भूसा-चारा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा पशुओं को खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। किसानों के मुताबिक, इस समय उनके खेतों में गन्ने की फसल लहलहा रही थी, लेकिन गौशाला से छोड़े गए जानवरों ने करीब 9 से 10 बीघा फसल पूरी तरह चोपट कर दी। किसानों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पहले ग्राम प्रधान से शिकायत की, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

सन्दिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

जन एक्सप्रेस प्रतापगढ़। जिले के कोहड़ी थाना इलाके के धत्रीपुर गांव निवासी राम चन्द्र का 21 वर्षीय बेटा वीरेन्द्र गौतम बुधवार शाम छ बजे बारात जाने के लिए कहकर घर से निकला था। देर रात वह एक बाइक समेत गम्भीर रूप से घायल अवस्था में पूरे क्षमा पुल के समीप मिला। जहां पर एम्बुलेंस के जरिये उसे सीएचसी कोहड़ी लाया गया। सीएचसी में उसकी हालत गम्भीर देख डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजन बाइक स्वामी के बेटे के साथ ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मौके पर मिली बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। इलाके में चर्चा है कि युवक तेज रफात से बाइक समेत विद्युत पोल में टकराया होगा जिससे उसकी मौत हुई होगी। फिलहाल अब ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आयेगा। वहीं बाइक के मालिक के बेटे ने रात में ही अपनी बाइक चोरी होने की तहरीर पुलिस को दी थी। फिलहाल कोहड़ी पुलिस सीसीटीवी खंगालने के साथ ही मामले की गम्भीरता से छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसओ कोहड़ी धननयन मुकदमा दर्ज कर मामले की जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी व इनामिया तीन अभियुक्त गिरफ्तार



जन एक्सप्रेस | प्रतापगढ़

जिले की जेठवारा थाने की पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में दर्ज मुकदमे में वाइल्ट व इनामिया तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। बता दें कि मध्यप्रदेश के सागर जिले के पश्चिमी निवासी सन्तोष शुक्ला की तहरीर पर जेठवारा पुलिस ने चार नामजद व पांच छ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। सन्तोष का आरोप था कि थाना

इलाके के कुटिलिया गांव निवासी बदरूल जमा पुत्र रफीउज्जमा द्वारा अपने पास रखा गया था। आरोप है कि उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया। पीड़ित द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह बचपन से ही अपने परिवार से अलग रह रहा है तथा लगभग बारह वर्ष से बदरूल जमा के यहां रहता है। लगभग चार वर्ष पूर्व बदरूल जमा पुत्र रफीउज्जमा, कहु पुत्र मुनीर, नईम पुत्र मुनीर निवासी कुटिलिया से डेहरेई, निजाम पुत्र जैनुद्दीन एवं पांच-छ: अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसका धर्म परिवर्तन कर उसका नाम शेर खान पुत्र उमर

रख दिया गया। पुलिस सरगमौ से अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। एसपी दीपक भूकर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एएसपी पश्चिमी बृजनन्दन राय व सीओ सदर करिश्मा गुप्ता के नेतृत्व में थाना प्रभारी जेठवारा विजय कान्त सत्यार्थी व स्याद टीम ने मुखबिर की सूचना पर पच्चीस पच्चीस हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त निजामुद्दीन उर्फ निजाम, सफीउज्जमा उर्फ कहु व नईमुद्दीन उर्फ नईम को थाना क्षेत्र अंतर्गत तान्त्रिक चौराहे के पास से गुरुवार को गिरफ्तार किया।

पर्दाफाश: कलियुगी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची पति के हत्या की साजिश, पत्नी व उसके प्रेमी समेत चार गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस | प्रतापगढ़

जिले के बाघराय थाना इलाके में एक कलियुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना इलाके के गोरीवा गांव निवासी संगीता पत्नी शोभमणि ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसका पति प्रधान पिंडू सिंह के यहां काम करता था। बीते 6 जनवरी को काम खत्म कर घर आते समय रास्ते में उस पर अज्ञात लोगों हमला कर घायल कर दिया। जिसके इलाज प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की हर पहलुओं से जांच कर रही थी। इसी बीच चायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गयी जिसके बाद पुलिस द्वारा विवेचना के



दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं मृत्यु के दृष्टिगत मुकदमे में सम्बंधित धारा की वृद्धि की गई। एसपी दीपक भूकर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एएसपी पश्चिमी व सीओ सदर के कुशल नेतृत्व में बाघराय पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए घटना में शामिल आरोपियों सचिन यादव, नागेश कुमार, तस्लीम व मृतक की पत्नी संगीता यादव व एक नाबालिग को थाना इलाके के गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे ग्राम गोरीवा के पास से गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया।

पुलिस ने इनके कब्जे से जेवरत व घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त सचिन यादव से जेवरों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसका मृतक शोभमणि की पत्नी संगीता से लम्बे समय से अवैध सम्बन्ध था। जिसकी जानकारी होने पर शोभमणि अपनी पत्नी संगीता को इस बात को लेकर रोज दबाव डालता व परेशान करता था। संगीता ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए जेवरत अपने प्रेमी को दिया ताकि उसे बेचकर पैसे की व्यवस्था

हो सके। जिसके बाद अभियुक्त सचिन यादव ने अपने साथी नागेश कुमार यादव, तस्लीम व अभिषेक गौतम के साथ मिलकर शोभमणि को मरवाने का सौदा कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसने बीस हजार रुपये उन लोगों को दिया और पचास हजार काम होने के बाद देने का वादा किया। बीते छ फरवरी को जब शोभमणि ग्राम प्रधान पिन्डू सिंह के घर से काम करके घर वापस आ रहा था तभी चारों आरोपियों ने गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे के पास रोक लिया। योजना के अनुसार सचिन, नागेश व अभिषेक गौतम पीछे से शोभमणि को पकड़ लिये और तस्लीम ने अपने पास लिये लोहे की राड से शोभमणि के सिर पर मारा जिससे शोभमणि मौके पर ही गिर गया और बेहोश हो गया और कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। फिलहाल पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया है।

सन्दिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

जन एक्सप्रेस प्रतापगढ़। जिले के कोहड़ी थाना इलाके के धत्रीपुर गांव निवासी राम चन्द्र का 21 वर्षीय बेटा वीरेन्द्र गौतम बुधवार शाम छ बजे बारात जाने के लिए कहकर घर से निकला था। देर रात वह एक बाइक समेत गम्भीर रूप से घायल अवस्था में पूरे क्षमा पुल के समीप मिला। जहां पर एम्बुलेंस के जरिये उसे सीएचसी कोहड़ी लाया गया। सीएचसी में उसकी हालत गम्भीर देख डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजन बाइक स्वामी के साथ ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। इलाके में चर्चा है कि युवक तेज रफात से बाइक समेत विद्युत पोल में टकराया होगा जिससे उसकी मौत हुई होगी। फिलहाल अब ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आयेगा। वहीं बाइक के मालिक ने रात में ही अपनी बाइक चोरी होने की तहरीर पुलिस को दी थी। फिलहाल कोहड़ी पुलिस सीसीटीवी खंगालने के साथ ही मामले की गम्भीरता से छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसओ कोहड़ी धननयन राय ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

होली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट, नमूने लेकर भेजा जांच को

जन एक्सप्रेस | प्रतापगढ़

जिले में आगामी पर्व होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क है। त्योहार पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा 19 से 28 फरवरी तक अभियान चलाते हुए बाजार में विक्रय किये जा रहे खोया, खाद्य तेल एवं वनस्पति, घी, गुड़िया, नमकीन समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हेतु जिला अधिहित अधिकारी अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में खाद्य सचल दल द्वारा जिले के विभिन्न बाजारों में स्थित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुये खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रहित किया जा रहा है। उसी क्रम में गुरुवार को कुण्डा तहसील के बाबूजंग बाजार स्थित लालजी



तिवारी की दुकान से खोया का एक नमूना संग्रहित करते हुए पन्द्रे हजार कीमत का लगभग साठ किलो खोया नष्ट कराया गया। वहीं ताजपुर बाजार स्थित वंशीलाल के यहां से सूजी (अन्नकूट गोल्ड) का एक नमूना संग्रहित किया गया। इस दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए दो खाद्य

प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया। साथ ही दो नमूने को संग्रहित कर विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को भेजा गया। खाद्य सचल दल में रोशन सिंह, सन्तोष कुमार दूबे, डॉ. तुलिका शर्मा, डा. शमशुन नेहा व शहाब उद्दीन सिद्दीकी खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जीरो फेटेलिटी अभियान के तहत दी गई यातायात नियमों की जानकारी

जन एक्सप्रेस | प्रतापगढ़

जिले में %जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट% अभियान और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (फरवरी-2026) के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में गुरुवार को एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर उपनिरीक्षक यातायात रामगो सिंह, उपनिरीक्षक यातायात सुधांशु पाठक, एंटी रोमियो प्रभारी, डायल-112 के अधिकारीगण एवं सदर पेशकार मुख्य आरक्षी चंद्रभूषण सिंह द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में साकेत पीजी कॉलेज के छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकगण को लाउंड डेयर के माध्यम से यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस दौरान वाहन चालकों को



निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट एवं चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, नशे की अवस्था में वाहन न चलाने तथा यातायात संकेतों एवं नियमों का पालन करने हेतु विशेष रूप से प्रेरित किया गया। साथ ही साइबर अपराधों की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा व

सशक्तिकरण से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया। यातायात पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य नागरिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उक्त जागरूकता अभियान जनपद में निरंतर संचालित किया जा रहा है।

सांसद की अध्यक्षता में निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न

जन एक्सप्रेस | प्रतापगढ़

जिले में गुरुवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक विकास भवन स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय सभागार में सम्पन्न हुई। जिसमें सांसद एसपी सिंह पटेल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधायक रानीगंज आरके वर्मा, विधायक जीतलाल पटेल, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्था, पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दिव्या मिश्रा तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधिगण के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान केन्द्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता से जुड़े योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा जन सुविधाओं से जुड़े अनेक सुझाव और समस्याओं को भी रखा गया।



जिसके समाधान के निर्देश समिति द्वारा अधिकारियों को दी गई। योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए एसपी सिंह पटेल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़ी जो शिकायतें व फीडबैक रखा गया है। उसे अधिकारी

उठाए गए स्थानीय समस्याओं एवं सुझावों पर विचार-विमर्श कर उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष एसपी सिंह पटेल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़ी जो शिकायतें व फीडबैक रखा गया है। उसे अधिकारी

गंभीरता से लेते हुए समय सीमा के अन्दर उसका समाधान कराएँ। विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए रोड मैप तैयार कर कार्य किए जाएँ। अधिकारी व जनप्रतिनिधि जिले के विकास के लिए आगे आकर टीम भाव से कार्य करें। जिससे कि विकास की दिशा में जिला अग्रणी रहे।

एनसीईआरटी विवाद पर शिक्षा मंत्री की सफाई, बोले

न्यायपालिका का अपमान करने की कोई मंशा नहीं

जन एक्सप्रेस/एजेसी। नई दिल्ली

एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका से जुड़े कथित विवादाित अध्याय को लेकर देश में उठे राजनीतिक और न्यायिक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मदे प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ हुआ उससे उन्हें गहरा दुख है और सरकार या शिक्षा मंत्रालय की ओर से न्यायपालिका का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने भयंसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई भी होगी।



न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू हो गई।

पूरा विवाद आखिर है क्या?

यह मामला एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब से जुड़ा है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित एक हिस्सा शामिल किया गया था। इस सामग्री को लेकर वरिष्ठ वकीलों और कई कानूनी विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि स्कूल के छात्रों को इस तरह की सामग्री पढ़ाना

सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा था कि किसी भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने संकेत दिया था कि यह एक सुनिश्चित प्रयास भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।

क्या बोले शिक्षा मंत्री धर्मदे प्रधान?

धर्मदे प्रधान ने कहा कि सरकार न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करती है और किसी भी शैक्षणिक सामग्री के जरिए संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ी सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया की जांच की जा रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अध्याय तैयार करने में शामिल लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, संस्थाओं को बदनाम करना नहीं।

शिक्षा मंत्रालय सचिव और एनसीईआरटी निदेशक को नोटिस

मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती जारी है। अदालत ने शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव और एनसीईआरटी निदेशक डॉ. दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन और अधिवक्ता आदिश सी अग्रवाल ने कहा कि न्यायपालिका ने सही कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार जैसी बातें शामिल करना वरिष्ठ अधिकारियों की बड़ी चूक है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि न्यायपालिका देश की महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री पर कानून अपना काम करेगा। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है और किसी भी तरह की लापरवाही को हलके में नहीं लिया जाएगा।

अब आगे क्या कार्रवाई होगी?

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पूरे मामले की समीक्षा कर रही है और अदालत के निर्देशों के अनुसार

डिजिटल होगी जनगणना 2027: मोबाइल और जियो-टैगिंग से होगा डेटा संग्रह

जन एक्सप्रेस/एजेसी। नई दिल्ली

जनगणना 2027 को पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके केंद्र में जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) नाम का विशेष डिजिटल पोर्टल होगा, जिसके जरिए दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक भारत की जनगणना का संचालन किया जाएगा। कागजी फॉर्म और रजिस्ट्रारों की जगह अब हाथ से चलने वाले उपकरण, जियो-टैगिंग मैपिंग टूल और एक केंद्रीकृत वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। करीब 32 लाख फील्ड कार्यकर्ताओं (गणनाकार और पर्यवेक्षक) मोबाइल डिवाइस के माध्यम से करोड़ों घरों से जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े एकत्र करेंगे। यह डाटा सीएमएमएस प्रणाली के जरिए तुरंत ट्रांसमिट, संकलित और सत्यापित किया जा सकेगा।

'किसान की सुरक्षा-सम्मान से ही भारत सफल होगा'



जन एक्सप्रेस/एजेसी। कन्नूर

केरल दौर पर पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्र सरकार को जनाकर घेरा। कन्नूर में एक कार्यक्रम के संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत तभी सफल हो सकता है जब हमारे किसानों का सम्मान और सुरक्षा हो। इतना ही नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन फाइलों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए किया ताकि वे एक ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करें जिससे भारतीय किसानों की 'बलि' चढ़

अमेरिका राष्ट्रपति पीएम को धमकी दे रहे थे: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि कृषि संबंधी मतभेदों के कारण भारत-अमेरिका समझौता बार महीने से रुका हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया, 'भारतीय सरकार अमेरिकी कंपनियों के लिए कृषि क्षेत्र खोलना नहीं चाहती थी। कुछ भी प्रगति नहीं हो रही थी और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे थे।' उन्होंने आगे दावा किया कि राष्ट्रपति के संबोधन के बाद उन्हें संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वे दो मुद्दे उठाना चाहते थे। उन्होंने कहा, 'एक मुद्दा एपस्टीन की उन 35 लाख फाइलों से संबंधित था, जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। ये फाइलें अमेरिकी सरकार द्वारा गुप्त रखी गई हैं और कथित तौर पर इनमें भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी शामिल है। दूसरा मुद्दा अमेरिका में अडानी का मामला था।'

जाएगी।

किसान सम्मेलन को राहुल ने किया संबोधित

लोकसभा में विपक्ष के नेता कन्नूर जिले के पेरावूर में किसानों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस सरल तथ्य को नहीं समझती कि किसान भारत की नींव हैं। उन्होंने कहा कि आईटी और अन्य क्षेत्रों के बारे में लंबे-लंबे व्याख्यान दिए जाते हैं, लेकिन नींव को मजबूत किए बिना कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'यदि आप नींव का सम्मान नहीं करते, तो कुछ भी नहीं

बन सकता। नींव बनाने वाले को सम्मान या सुरक्षा नहीं मिलती। हम हर दिन भोजन करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उसे हमारे खाने की मेज पर कौन रखता है।' राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक ऐसा समझौता किया, जो नींव खोदने जैसा था। उन्होंने कहा, 'भारतीय किसान छोटे किसान हैं और उनमें मशीनीकरण का स्तर कम है। अमेरिकी किसानों के पास विशाल खेत हैं और उनमें मशीनीकरण का स्तर उच्च है। अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करना एक आपराधिक कृत्य है।'

डीएनपीए कॉन्क्लेव 2026: प्लेटफॉर्मस स्वेच्छ से रेवेन्यू साझा करें, अन्यथा कई देश कानूनी राह दिखा चुके: अश्विनी वैष्णव

जन एक्सप्रेस/एजेसी। नई दिल्ली

भारत के शीर्ष प्रकाशक समूहों की डिजिटल इकाइयों के संगठन डीएनपीए द्वारा डीएनपीए कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन गुरुवार को किया गया। डिजिटल मीडिया के दौर में समाचार माध्यमों की भूमिका कैसी हो? इस विषय पर यहां विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूरी दुनिया के मीडिया जगत के लिए यह महत्वपूर्ण दौर है। यह सही निर्णय लेने का समय है। यह जरूरी है कि आम सहमति बने, अच्छे विकल्प सामने आएँ और अच्छी सिफारिशें मिलें ताकि भविष्य की नीतियों को आकार दिया जा सके।



पहचान, न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका जैसी संस्थाओं तक जाता है। समाज के अलग-अलग अंग और संस्थाएं विश्वास के सिद्धांत पर काम करती हैं। मीडिया घरानों के लिए भी बुनियादी सिद्धांत यही रहता है कि वह निष्पक्ष और जिम्मेदार रहे। मीडिया के समक्ष खतरों भी मौजूद हैं। जैसे- डीप फेक, गलत सूचनाओं का प्रवाह। हर समाज इस तरह के खतरों से जूझ रहा है। जो संस्थाएं शताब्दियों से मौजूद हैं, उन्हें इन खतरों से कैसे बचाए रखा जाए, यह बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन सेप्टी इसके लिए बहुत जरूरी है।

मानव समाज भरोसे की संस्थाओं पर टिका है

बदलते दौर में समाचार माध्यमों की भूमिका पर केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि पुरा मानव समाज भरोसे की संस्थाओं पर टिका है। यह भरोसा परिवार से शुरू होता है और सामाजिक

'रेवेन्यू भी निष्पक्ष तरीके से साझा किया जाए'

उन्होंने कहा कि संसदीय समितियों और न्यायपालिका भी लोगों के सामने मौजूद खतरों को लेकर चिंतित हैं। अगर किसी यूजर की कोई शिकायत है, तो उसे कैसे सुना जाए और उनकी हिफाजत करने का तंत्र क्या होगा, इस पर चर्चा जरूरी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस के व्यावसायिक मॉडल पर बात करते हुए उन्होंने जोर दिया कि खबरों के रचनाकारों, परंपरागत मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और शोधार्थियों के साथ रेवेन्यू निष्पक्ष तरीके से साझा किया जाना चाहिए। इसके लिए नीतिगत ढांचे की आवश्यकता जताते हुए और टेक कंपनियों को आगाह करते हुए वैष्णव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'मैं सभी प्लेटफॉर्मस से अपनी रेवेन्यू-शेयरिंग नीतियों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगा क्योंकि यह आज पूरे समाज की एक प्रमुख चिंता है। यदि यह स्वेच्छ से नहीं किया जाता है, तो ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इसे कानूनी तरीके से करने का रास्ता दिखाया है।' इसके लिए नीति बनाना जरूरी है। जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास मौलिक कंटेंट है, वह उनकी बौद्धिक संपदा है, जिसका सम्मान होना चाहिए। बौद्धिक संपदा का सम्मान नहीं होगा, तो समाज का विकास भी नहीं हो सकेगा।

खबरों की प्रामाणिकता, बच्चों की सुरक्षा, सिंथेटिक कंटेंट से बचाव भी जरूरी है और इसके लिए निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है।

'सत्यापन का ध्यान रखना जरूरी'

वैष्णव ने कहा कि उदाहरण के लिए होटल में आने वाले ग्राहक का होटल प्रबंधन सत्यापन करता है, उसी तरह

'अब नहीं चलेगी परमाणु धमकी', भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चेतावनी



जन एक्सप्रेस/एजेसी। चंडीगढ़

भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े सैन्य तनाव के बीच भारतीय सेना ने साफ संदेश दिया है कि अब पाकिस्तान की परमाणु धमकियों का कोई असर नहीं होगा। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की रणनीति बदल चुकी है और अगली कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा कड़ी होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि जमीन पर निर्णायक जीत हासिल करने की तैयारी में है।

सेना अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल जीत का जश्न नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी का प्रदर्शन था। उन्होंने बताया कि सेना अब तकनीकी आत्मनिर्भरता पर तेजी से काम कर रही है। खास तौर पर ड्रोन तकनीक, आधुनिक हथियार और 100 प्रतिशत उपकरण तैयार स्थिति में रखे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी ताकत भारतीय जवान ही हैं, जिनकी ट्रेनिंग लगातार मजबूत की जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और सेना पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उनका साफ संदेश था कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई गलती की तो इस बार जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा होगा कि दुश्मन लंबे समय तक याद रखेगा।

क्या कहा सेना के पश्चिमी कमान प्रमुख ने?

पठानकोट में आयोजित एक सैन्य सम्मान समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी बड़े आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन भारतीय सेना ने उनके सैन्य और हवाई ठिकानों को भी तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए थे कि पाकिस्तान को सीधे और अन्य देशों के जरिए युद्धविराम की मांग करनी पड़ी। सेना प्रमुख ने कहा कि अगली बार जवाब और ज्यादा कठोर होगा।

फडणवीस ने ताड़देव-नागपाड़ा-मुंबई सेंट्रल फ्लाईओवर का किया उद्घाटन

जन एक्सप्रेस/एजेसी। मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को ताड़देव-नागपाड़ा-मुंबई सेंट्रल फ्लाईओवर का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह फ्लाईओवर दक्षिण मुंबई में पूर्व-पश्चिम को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण लिंक है, जो यात्रियों को आवाजाही के लिए एक सुगम और वैकल्पिक रास्ता प्रदान करेगा। मुंबई सेंट्रल पर स्थित 130 साल पुराना ब्रिटिश कालीन पुल काफी जर्जर हो चुका था। प्रशासन ने इसे खतरनाक



घोषित करने के बाद तोड़ दिया था। पिछले दो वर्षों से इस मार्ग पर कनेक्टिविटी बाधित थी। अधिकारियों

का मानना है कि इस नए फ्लाईओवर के शुरू होने से जहांगीर बोमन बेराम रोड (बेलासिस रोड), डॉ. दादासाहेब भडकमकर मार्ग (ग्रॉट रोड), साठे बापूवल मार्ग और महालक्ष्मी स्टेशन पुल पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा।

फ्लाईओवर की खासियतें

इस फ्लाईओवर की कुल लंबाई 333 मीटर है। इसमें पूर्वी हिस्सा 138.39 मीटर, पश्चिमी हिस्सा 157.39 मीटर और रेलवे सीमा के भीतर का हिस्सा 36.90 मीटर लंबा है।

कृषि मंत्री ने पेड़ लगाने का किया आग्रह, कहा, इससे मेरा जन्मदिन सार्थक हो जाएगा

जन एक्सप्रेस/एजेसी। नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन आने वाला है। इस बीच क उन्होंने गुरुवार को अपने कार्यक्रमों से अपील करते हुए कहा कि वे उनके जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी फोटो खींचकर उन्हें भेजें, जिससे उनका जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रिय बहन-भाइयों और भांजे-भांजियों, हमारा

जीवन किसलिए है। वो कैसे सफल और सार्थक होगा। वो सार्थक होगा किसी अच्छे उद्देश्य के लिए जीने से। पर्यावरण का संरक्षण मेरे जीवन का एक पवित्र उद्देश्य रहा है। इसलिए मैं रोज पौधा लगाता हूँ। 5 मार्च को मेरा जन्मदिन है। आप स्नेह के कारण, प्रेम और आत्मीयता के कारण उसे उत्साह से मनाते भी हैं। राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के कारण कई कार्यकर्ता होर्डिंग लगा देते हैं। कई शील, श्रीफल और स्मृति चिह्न लेकर आते हैं। लेकिन, 5 मार्च को इस बार मेरी आप

मैं बीते 5 वर्षों से प्रतिदिन पौधा लगा रहा हूँ: चौहान

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे जन्मदिन पर न फूल-मालाएं, न शील, न श्रीफल, न स्मृति चिह्न, न होर्डिंग, बस इस दिन एक पेड़ जरूर लगाएं। उसका फोटो अपलोड कर दें या मुझे भेज दें। मेरा जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। हर सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन जब मैं गहराई में सोचता हूँ तो पौधा लगाना इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। पेड़ हर एक के काम आते हैं। मनुष्यों को जीने के लिए जरूरी हैं। कीट-पतंगें और पक्षी उनका घर और भोजन हैं पेड़। पशुओं को छाय भी देते हैं और भोजन भी देते हैं। धरती का श्वाभ भी है और धरती का जीवन भी है पेड़। पौधा लगाया इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है और इसीलिए तो मैं पौधा लगाता हूँ। आप पौधा लगाएं, केवल मेरे जन्मदिन पर नहीं, अपने जन्मदिन पर भी। मैं बीते 5 वर्षों से प्रतिदिन पौधा लगा रहा हूँ।

सबसे अपील है कि जन्मदिन को भी उद्देश्यपूर्ण बनाएं।

गाजियाबाद संपत्ति कर विवाद: हाईकोर्ट ने पूर्व पार्षदों की याचिका खारिज की

बड़े टैक्स से भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार के खिलाफ जनता का बड़ा आक्रोश

महापौर सुनीता दयाल ने पूर्व पार्षदों पर फौड़ा ठीकरा

जन एक्सप्रेस। गाजियाबाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद नगर निगम द्वारा संपत्ति कर (हाउस टैक्स) में बढ़ोतरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी और अन्य पूर्व पार्षदों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें नगर निगम के नए वर्गीकरण और किराया दरों में वृद्धि को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस फैसले में 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई बढ़ी हुई दरों पर टैक्स वसूली का रास्ता साफ हो गया है। जिससे शहर के करीब 5.5 से 6 लाख घरवालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है। होली पर्व से पहले आए इस निर्णय ने

जनपदवासियों की होली फीकी कर दिया है। जनता का गुस्सा अब भाजपा नेताओं और महापौर पर फटने की आशंका है। भाजपा के सांसद,विधायक से लेकर प्रचंड बहुमत से निगम सदन में बहुमत वाली ट्रिपल इंजन सरकार के बावजूद जनता को भारी भरकम टैक्स की मार उठाने के लिए मुसीबत बनने वाला है। अब महापौर सुनीता दयाल उच्च न्यायालय के निर्णय के पीछे पूर्व पार्षदों की याचिका बताकर सारा ठीकरा फोड़ दिया है। जबकि पूर्व पार्षद इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले जाने की बात कही है। गाजियाबाद नगर निगम ने पिछले साल अप्रैल 2025 से संपत्ति कर की नई दरें लागू करने का फैसला लिया था। यह फैसला 14 साल बाद लिया गया, क्योंकि आखिरी बार टैक्स दरें 2001 में तय की गई थीं और 2015 तक कोई बदलाव नहीं हुआ था। निगम प्रशासन द्वारा नई प्रणाली में शहर को सड़कों की चौड़ाई और विकास स्तर के आधार पर तीन



श्रेणियों ए, बी और सी में बांटा गया। श्रेणी ए में पॉश इलाके, बी में मध्यम और सी में स्लम या कम विकसित क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके अलावा, न्यूनतम मासिक किराया दरों में वृद्धि की गई और पुरानी स्टूटों को समाप्त कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ जून 2025 में पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी, हिमांशु मित्तल और अन्य न्यायिक याचिका सहित अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया। याचिकाकर्ताओं का

कौन है जिम्मेदार ?

इस टैक्स बढ़ोतरी की मुख्य जिम्मेदारी नगर आयुक्त पर है, जिन्होंने राज्य सरकार के निर्देश पर फैसला लिया। राज्य सरकार ने धारा 116 के तहत आयुक्त को निर्देश दिए कि निगम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि पुरानी दरों से राजस्व घटा हो रहा था और विकास कार्य प्रभावित थे। पूर्व पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन और मेयर ने जनता की चिंताओं को नजरअंदाज किया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। विपक्षी पार्टियां इसे सरकार की नीति का हिस्सा मान रही हैं, जबकि निगम अधिकारियों का कहना है कि यह शहर के विकास के लिए जरूरी कदम है। कुल मिलाकर, राज्य सरकार को नगर आयुक्त की भूमिका प्रमुख है, जबकि सदन ने शुरुआत में विरोध किया लेकिन लागू होने दिया।

जनता पर कितना बढ़ेगा टैक्स ?

टैक्स बढ़ोतरी की कोई निश्चित प्रतिशत नहीं बताई गई, लेकिन कुछ इलाकों में यह 3 से 4 गुना तक हो सकती है, खासकर डीएम सर्किल रेट के अनुरूप। नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हैं, और फरवरी 2026 तक छूट के साथ वसूली हो रही है। श्रेणी ए पॉश इलाके में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी, जबकि सी स्लम में कम बोझ रखा गया है ताकि गरीब प्रभावित न हों। उदाहरण के लिए, पुरानी एक समान दरों की जगह अब संपत्ति के प्रकार आवासीय, व्यावसायिक और स्थान के आधार पर गणना होगी। जिन्होंने पहले बढ़ी दरों पर भुगतान किया, उनकी राशि आगे समायोजित की जाएगी। जनपद के लगभग 6 लाख घरदाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन निगम का दावा है कि इससे शहर की सेवाएं बेहतर होंगी। पहले 20 प्रतिशत छूट की धराकश की गई थी, लेकिन विरोधियों ने इसे 'लौलीपाप' बताया।

जनहित के मुद्दे को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे

पूर्व पार्षद हिमांशु मित्तल ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि यह फैसला जनता की जेब पर 'ढाका' है। वहीं, नगर निगम का कहना है कि यह फैसला निगम को मजबूत बनाएगा और विकास कार्यों में तेजी लाएगा। आर.के.ए.ए. और व्यापारी संघ पहले से विरोध कर रहे हैं, और अब वसूली तेज होने से असंतोष बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में हर दो साल में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रवधान रहेगा। यह मामला गाजियाबाद में टैक्स सुधारों की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन जनता के लिए चुनौतीपूर्ण भी।

निगम अधिनियम, 1959 की धारा 174 का हवाला देते हुए कहा कि नगर आयुक्त को संपत्तियों का वार्षिक मूल्यांकन और किराया दरें निर्धारित करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है। शहर का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण तर्कसंगत और पारदर्शी है, क्योंकि यह सड़कों की चौड़ाई जैसे 20 मीटर से अधिक के आधार पर किया गया। कोर्ट ने नोट किया कि नई दरें लागू करने से पहले जनता से आपत्तियां मांगी गईं और 318 आपत्तियों का निराकरण किया गया। साथ ही, याचिका को जनहित के बजाय राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित माना गया। राज्य सरकार का धारा 116 के तहत हस्तक्षेप भी कानूनी और उचित उद्देश्य था, क्योंकि इसका उद्देश्य जनहित और निगम के राजस्व के बीच संतुलन बनाना था। कोर्ट ने कहा कि सर्वजनिक सेवाओं जैसे स्वस्थ, परिवहन, बिजली गिड के बेहतर संचालन के लिए राजस्व जुटाना अनिवार्य है।